04 - एसआईआर पर बंगाल का दृश्य डरावना

05 - डॉ. मोहन यादव सरकार के बेमिसाल दो साल

06 - सत्ता की चकाचौंध में 'तंत्र' कहां खो गया है?

07 - लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 21 से 26 दिसंबर तक लगेगा आदि बाजार

A Daily News Magazine

इंदौर

शनिवार, 13 दिसंबर, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 77, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

डिस्कनेक्ट बिल-2025: दफ़्तर के बाद नहीं आयेंगे बॉस के फोन!

पंकज श्रीवास्तव

डिस्कनेक्ट बिल 2025 कर्मचारियों को ऑफिस आवर्स के बाद काम से पूरी तरह अलग होने का अधिकार देता है। क्या यह बिल पास होगा और क्या अब दफ़्तर के बाद बॉस के फ़ोन और मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं होगा?

दफ़्तर में काम ख़त्म होने के बाद भी बॉस से मिलने वाले आदेश-निर्देश बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इसने वर्क-लाइफ बैलेंस बुरी तरह बिगाड़ दिया है। 6 दिसंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया है जिसका मक़सद इस संदर्भ में क़ानून बनाना है।

आज दफ़्तरों में काम करने वाले करोड़ों लोग ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट गले में पड़े पट्टे की तरह हो गये हैं। ऐसा लगता है कि 24 घंटे दफ़्तर में ही उलझे हुए हैं। छुट्टी के दिन बाज़ार में ख़रीदारी करते वक़्त भी बॉस फ़ोन करके कोई अर्जेंट काम बता सकता है। यह माहौल कर्मचारियों की सेहत पर बेहद बुरा असर डाल रहा है। बिल में कुछ ख़ास बात है-

1. डिस्कनेक्ट बिल-2025 कर्मचारियों को काम के घंटों के बाहर डिस्कनेक्ट करने का कानूनी हक देता है।

2. नियोक्ता इमरजेंसी की स्थिति में कॉल कर सकता है लेकिन कर्मचारी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

3. बिल उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव देता है जो डिस्कनेक्ट होने के अधिकार की अनदेखी करती है।

सरल शब्दों में बिल अधिकार देता है कि अगर आपका बॉस रविवार को कॉल करे, तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बिना डर के कि प्रमोशन पर असर पड़ेगा। यानी मक़सद है काम के घंटों के बाद और छुट्टियों पर काम से जुड़े कॉल, ईमेल या मैसेज का जवाब न देने का हक देना। मतलब, कर्मचारी ऑफिस के बाहर वाक़ई 'ऑफ' हो सकते हैं। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा क्षेत्र की प्रतिनिधि हैं लेकिन लगता है कि पुणे में काम के दबाव से जान गँवाने वाली एना की तस्वीर उनके जेहन से उतरी नहीं है।

केरल की रहने वाली 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) एना सेबेस्टियन की 21 जुलाई 2024 को अचानक मौत हो गयी थी। वजह थी काम का अत्यधिक दबाव। यह मामला देश भर में चर्चित हुआ जब एना की माँ अनीता आगस्टाइन ने सितंबर में ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा- लंबे काम के घटों ने उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया।

अनीता ने अपील की कि EY कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता दे, ताकि उत्पादकता के नाम पर जिंदगियाँ न बर्बाद हों।

यह पत्र ईवाई के पुणे ऑफिस से लीक हो गया और जल्दी ही इंटरनेट पर छा गया। वैसे, पूरी दुनिया में ये बहस चली है और कई देशों में रास्ते भी निकाले गये हैं। फ्रांस ने 2017 में सबसे पहले कानून बनाया- 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी को रात में मैसेज करने की मनाही। बेल्जियम और पुर्तगाल ने भी कानून बनाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में डिस्कनेक्ट बिल पास किया। वैश्विक नौकरी प्लेटफॉर्म इंडीड ने पिछले साल भारत में एक सर्वे किया था। इसके मुताबिक- 88 फ़ीसदी लोगों को काम ख़त्म होने के बाद मैसेज-कॉल आते हैं। 85 फ़ीसदी लोगों के पास छुट्टी के दौरान ऑफिस से कॉल आता है। 79 फ़ीसदी लोग डरते हैं कि अगर ऑफ़िस से आये मेल या मैसेज का जवाब न दिया तो नौकरी जा सकती है। प्रमोशन पर असर पड़ सकता है।

63 फ़ीसदी जेन ज़ेड कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि उनकी डिस्कनेक्ट करने का अधिकार का सम्मान न किया जाए तो वे नौकरी छोड़ने पर विचार करेंगे। लेकिन 66 फ़ीसदी मानते हैं कि काम ख़त्म होने के बाद संपर्क करना उत्पादकता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है।

यानी कंपनियों के लिए मुनाफ़ा अहम है जिसके लिए इंसान को रोबोट बनने पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ समय पहले इंफोसिस को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा है, यंगस्टर्स को 70 घंटे वर्कवीक करना चाहिए। इसका एक और पहलू भी है। 12 घंटे की शिफ़्ट का कर्मचारियों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। 12 घंटे शिफ्ट कार्यकुशुलता घटाती है। सतर्क रहने की क्षमता हटती है। ग़लतियों की आशंका बढ़ जाती है। इतने अध्ययनों के बावजूद नये श्रम क़ानूनों में एक दिन में बारह घंटे काम कराने की इजाज़त दी गयी है। जबकि पुराने क़ानून के हिसाब से एक दिन में आठ घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता था। अमेरिका में उन्नीसवीं सदी में एक आंदोलन चला था- 'एट आवर्स मूवमेंट।' यानी 'आठ घंटे काम, आठ घंटे आराम, आठ घंटे मनोरंजन!' एक सभ्य समाज में दिन इसी तरह होना चाहिए। दरअसल, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका में एक विशाल मज़दूर वर्ग पैदा हुआ था। उस समय अमेरिका में मज़दूरों को 12 से 18 घंटे तक खटाया जाता था। बच्चों और महिलाओं का 18 घंटों तक काम करना आम बात थी। अधिकांश मज़दूर अपने जीवन के 40 साल भी पूरे नहीं कर पाते थे। अगर मज़दूर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे तो उन पर निजी गुण्डों, पुलिस और सेना से हमले करवाये जाते थे! 1877 से 1886 तक मज़दूरों ने अमेरिका भर में आठ घंटे के कार्यदिवस की माँग पर एकजुट और संगठित होना शुरू किया। 1886 में शिकागो में खूनी प्रदर्शन हुआ, कई लोग मारे गए। कई मज़दूरों को फाँसी दी गयी। एक मई को मज़दूर दिवस उसी की याद में मनाया जाता है। लेकिन अंत में मज़दूरों की जीत हुई। 1938 में अमेरिका में कानून बन गया जिसके मुताबिक़ हफ्ते में 40 घंटे काम तय हुए। इससे ज्यादा काम कराने पर दोगुना मज़दूरी देना तय हुआ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कहता है- 8 घंटे काम, 48 घंटे हफ्ते- इससे ज्यादा नहीं।

भारत 1919 से ही ILO का सदस्य है लेकिन लगता है कि क़ानून की मूल भावना भुला दी गयी है। जब दुनिया में हफ़्ते में चार दिन काम कराने पर बहस हो रही है तो भारत में बारह घंटे काम कराने की छूट देने वाले लेबर कोड लागू हुए हैं। फिर भी डिस्कनेक्ट बिल एक उम्मीद है कि इस गंभीर मुद्दे की गूँज संसद तक पहुँच गयी है। यह अलग बात है कि प्राइवेट मेंबर बिल पास होने की उम्मीद न के बराबर होती है। ऐसा कोई भी बिल तभी क़ानून बन सकता है जब सरकार भी रुचि ले। यानी गेंद सरकार के पाले में है जो नये श्रम क़ानूनों के ज़रिए 12 घंटे काम कराने की छूट का जश्न मना रही है। कोई उम्मीद करे भी तो कैसे।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

मैं आऊंगा
महासागर पार
करके भी

मैं आऊंगा
आसमान छूता
शिखर पार करके भी

मैं आऊंगा
भीषण जंगल
पार करके भी

मैं आऊंगा
बंधन की सारी सीमाएं
लांघकर भी

मैं आऊंगा
ज्वालाओं में
जलते हुए भी ।

-दुर्गाप्रसाद झाला

मप्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर गिनाईं उपलब्धियां

नक्सलवाद खत्म कर मजबूत किया: सीएम मोहन यादव

भोपाल (नप्र)। मोहन सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे हो गए हैं। इन दो सालों में सरकार ने कई नई शुरुआत की है। साथ ही कई उपलब्धियां हासिल की है। सरकार ने दो साल पूरे होने के पूर्व ही एमपी से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही वर्षों पुरानी समस्या गैस कचरा का निस्तारण भी सरकार ने किया है। साथ ही आमलोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिए साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य, साइबर तहसील 2.0 की शुरुआत हुई।

नक्सलवाद को किया खत्म- सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसी समय में लॉ एंड ऑर्डर बड़ी समस्या थी। 17-17 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती था। मंत्री तक की हत्या की गई। हमने केंद्र के डेडलाइन से पहले ही मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने भी आगे आकर बालाघाट में ड्यूटी के लिए पहल की इसकी वजह से हमने सफलता पाई है।

सिंचाई का रकबा बढ़ रहा- मोहन यादव के कार्यकाल में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए दो बड़े काम हुए हैं। दो नदी जुड़े परियोजनाओं की नींव रखी गई। वर्षों से प्रस्तावित पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ परियोजना के विवादों को राजस्थान के साथ सुलझाया। इसके बाद परियोजना की नींव रखी गई। इसके साथ ही बुंदेलखंड को केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की सौगात दी गई। इससे एमपी और यूपी दोनों को फायदा होगा।

गौवंश के लिए भी काम- इसके साथ ही सरकार ने इन दो सालों में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025 स्वीकृत की। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एमपी सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ। गौ-वंश को मिलने वाली आहार राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया। साथ ही हर महीने गौशालाओं के खाते में 50 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।

आधुनिक नगर विकास की दिशा में बढ़ाए कदम- वहीं, मोहन सरकार ने इन दो सालों में आधुनिक नगर विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनमें दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। पहला- इंदौर, उज्जैन देवास और धार है। दूसरा- भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और ब्यावरा है। साथ ही पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख आवास बन रहे हैं।

ग्राम पंचायतों में किसान समृद्धि केंद्र की होगी स्थापना- मोहन सरकार ने पंचायतों में किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना कर रही है। हर विकासखंड में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत 155 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामों का चयन हुआ है। साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में विकेंद्रीकृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है।

पर्यटन के क्षेत्र में भी काम

इसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर चीता कॉरिडोर बनेगा। कूनो के बाद गांधी सागर में चीतों को बसाया गया है। साथ ही रातापानी और और माधव नेशनल पार्क की स्थापना की गई। पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा और पीएमश्री वायु पर्यटन सेवा की शुरुआत की गई। भोपाल के बड़े तालाब में शिकारा की शुरुआत की गई।

भोपाल में पहली बार जीआईएस

सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहले भोपाल में जीआईएस नहीं होती थी। भूतो न भविष्यति इसी साल फरवरी में भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) हुई। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से भी निवेश आया है। इसी का परिणाम है कि निवाड़ी जैसे छोटे जिले में इस्पात कारखाना खुल रहा है। झाबुआ में खाद बनाया जा रहा है। नीमच में भारत ही नहीं दुनिया का पंप स्टोरेज बना है, जिसका कार्य दो साल में पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में पहले जीआईएस सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसे उनकी सरकार ने लागू किया।

केंद्रीय कैबिनेट में हुए अहम फैसले

2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11718 करोड़ रुपये की मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कैबिनेट ने शुक्रवार को तीन महत्वपूर्ण फैसलों का मंजूरी दी। कैबिनेट ने जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री मंडल ने कोयला लिंकेज नीति में सुधार के लिए कोलसेटू नीति को भी मंजूरी दी है। सरकार ने खोपरा 2025 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी नीतिगत मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनगणना 2027 की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास होगा। जनगणना 2027 अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना केंद्र का विषय है। कोविड महामारी के कारण जनगणना 2021 आयोजित नहीं की जा सकी। इससे पहले 16 जून 2025 को जनगणना 2027 की राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। जनगणना 2027 की अनुमानित लागत 11,718 करोड़ रुपये होगी

दो चरणों में होगी जनगणना

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को होगी। बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 को होगी। वैष्णव ने कहा, जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

- **मनरेगा का बदल गया नाम,अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया-** केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। सरकार ग्रामीण गरीबों को सालाना 125 दिन काम की गारंटी देने वाला विधेयक पेश करेगी, जिसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि मनरेगा के तहत पहले 100 दिनों के काम की गारंटी मिलता था। सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। सूत्रों के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करके 240 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है।
- **रेलवे ने इस साल 3.02 करोड़ फेक-आईआरसीटीसी अकाउंट बंद किए: अश्विनी वैष्णव-** रेलवे ने जनवरी 2025 से अब तक 3.02 करोड़ संदिग्ध आईआरसीटीसी अकाउंट बंद कर दिए हैं। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा में दी ।यह कदम टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है।

- देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर एक्शन

4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर सस्पेंड

- डीजीसीए की एयरलाइन सीईओ से दूसरे दिन भी पूछताछ, बेंगलुरु एयरपोर्ट से आज 54 फ्लाइट कैंसिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में फ्लाइट कैंसिल को लेकर जारी संकट के बीच लगातार एक्शन हो रहा है। डीजीसीए (नागरिक उड्डयन नियामक) ने शुक्रवार को एयरलाइन की

सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है।

इधर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स आज लगातार दूसरे दिन डीजीसीए के सामने पेश होंगे। इससे पहले गुरुवार को पीटर से अधिकारियों ने करीब 2 घंटे की पूछताछ की थी। इसमें ऑपरेशंस, क्रू मैनेजमेंट, रिफंड, मुआवजे से जुड़े सवाल-जवाब किए गए।

वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट से शुक्रवार को इंडिगो की 54 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। इनमें 31 आने वाली (अराइवल) और 23 जाने वाली (डिपार्चर) फ्लाइट शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थीं।

गोपीनाथ बोले- इंडिगो संकट ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा- इस बीच, देश में कम किराए वाली विमान सेवा शुरू करने वाले कैप्टन गोपीनाथ ने कहा कि इंडिगो संकट शायद इसलिए बढ़ा, क्योंकि एयरलाइन संचालकों में घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था।

पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का 90 की उम्र में निधन

लातूर (एजेंसी)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को 90 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लातूर में सुबह 6.30 बजे अंतिम सांस ली। शिवराज पिछले कुछ

दिनों से बीमार चल रहे थे। लातूर में उनके घर देवघर में उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाटिल का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। शिवराज के परिवार में उनके बेटे शैलेश, बहू अर्चना और दो पोतियां हैं। पाटिल लातूर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे। शिवराज को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का विश्वासपात्र माना जाता था। वे 1980 के दशक में इंदिरा और राजीव की सरकारों में रक्षा मंत्री रहे।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची भूकंप से जुड़ी याचिका

- बेंच ने पूछा- क्या सबको चांद पर भेज दें, यह सरकार का काम, हमारा नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि भारत की 75 प्रतिशत आबादी हाई सिस्मिक जोन में है। इसलिए अधिकारियों को भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के निर्देश दिए जाएं।

इस दौरान याचिकाकर्ता ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच से कहा कि पहले यह माना जाता था कि सिर्फ दिल्ली हाई सिस्मिक जोन में है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर भूकंप आते हैं तो क्या सबको चांद पर भेज देना चाहिए। यह पॉलिसी से जुड़े काम हैं। इसका ध्यान सरकार को रखना है। हम ऐसा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि हाल ही में जापान में एक बड़ा भूकंप आया था। इस बात पर बेंच बोली- पहले हमें इस देश में ज्वालामुखी लाने होंगे, फिर हम इसकी तुलना जापान से कर सकते हैं।

- **सुप्रीम कोर्ट बोला- करूर भगदड़ की निष्पक्ष जांच होना जरूरी, कमेटी में तमिलनाडु का कोई व्यक्ति नहीं होगा,** -सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करूर भगदड़ मामले में पहले दिए गए अपने निर्देश को बदलने से इनकार कर दिया। अदालत ने निर्देश दोहराते हुए कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी करने वाले सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य तामिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने की। विजय की पार्टी टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने सीबीआई जांच के आदेश पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया।

अन्ना हजारे लोकायुक्त की मांग को लेकर 30 जनवरी से अनशन पर बैठेंगे

मुंबई (एजेंसी)। अन्ना हजारे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर आमरण अनशन की घोषणा की है। अन्ना 30 जनवरी से अपने गाँव रालेगण सिद्धि में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। अन्ना ने इसे अपना आखिरी आंदोलन बताया है। दरअसल अन्ना 2022 में भी इस मांग को लेकर अन्ना अनशन पर बैठे थे। उस समय उन्होंने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री की मध्यस्थता के बाद अनशन तोड़ा था।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 27 °c
न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 13 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

देश का दिल मध्यप्रदेश, दिल खोल कर स्वागत को है तैयार : मुख्यमंत्री

सीएम ने नई दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन परिसर में 3 दिवसीय मध्यप्रदेश उत्सव का भोपाल से वर्चुअली किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन परिसर में 3 दिवसीय मध्यप्रदेश उत्सव का भोपाल से वर्चुअली शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी को देश के दिल मध्यप्रदेश में आमंत्रित करते हुए कहा कि हम दिल खोलकर आपके स्वागत के लिये तैयार हैं। नई दिल्ली में अपर मुख्य सचिव एवं विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन श्रीमती रश्मि अरूण शमि और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास जताया कि मध्यप्रदेश उत्सव देखने के बाद सभी प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता का वास्तविक आनंद लेने के लिये जरूर मध्यप्रदेश आएंगे। उन्होंने पर्यटकों को महाकाल लोक में दर्शन करने, टाइगर रिजर्व सफारी का आनंद लेने, ओरछा एवं मांडू की आध्यात्मिकता का अनुभव करने के साथ पचमढ़ी के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिये आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के स्वच्छतम शहर इंदौर की सैर करें और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाएं।

मध्यप्रदेश उत्सव में विशेष

मध्यप्रदेश भवन परिसर में अगले 3 दिनों तक भव्य मध्यप्रदेश उत्सव मनाया जाएगा। इसमें मध्यप्रदेश की कला-संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प और खान-पान के स्टॉल लगाये गये हैं। यहां लगी प्रदर्शनियों में प्रदेश की विकास यात्रा, एक जिला-एक उत्पाद और जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं देखी जा सकती हैं। वनोपज से तैयार हर्बल उत्पाद भी प्रदर्शित किये गये हैं। अपने साथ लेकर जाइए। मध्यप्रदेश का हस्त शिल्प, कलाकृतियां और विभिन्न अंचलों के स्वादिष्ट व्यंजन इस मेले की यूएसपी हैं। इस उत्सव में मध्यप्रदेश पुलिस बैंड पहली बार प्रस्तुति दे रहा है। उत्सव में प्रदेश के टेक्स्टाइल को शो-केस करते हुए फैशन-शो भी आयोजित किया गया है। पारंपरिक व्यंजनों के फूड स्टॉल प्रदेश के असली स्वाद से यहां आने वालों को परिचित करवा रहे हैं। उत्सव में प्रदेश के लोक गीत और लोक नृत्य पूरे जोश और उल्लास के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।

मोबिलिटी और नई तकनीक क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक : सीएम

मुख्यमंत्री ने उज्जैन के ग्राम नलवा में मोबिलिटी स्टेशन का भोपाल से वर्चुअली किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के ग्राम नलवा स्थित श्री गायत्री पेट्रोलियम-मोबिलिटी स्टेशन का मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने प्रतिष्ठान के संचालक श्री गोविंद सिंह आंजना को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष-2028 के सिहंस्थ और उज्जैन-इंदौर-देवास के सम्मिलित रूप से मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकास से भविष्य का पश्चिमी मध्य प्रदेश आकर ले रहा है। क्षेत्र में रोड नेटवर्क और औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। क्षेत्र की गतिशीलता को सुनिश्चित करने में फ्यूल और मोबिलिटी तथा नई तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री गायत्री मोबिलिटी स्टेशन, गुणवत्ता और सेवा भाव के साथ क्षेत्र की प्रगति में योगदान देगा। ग्राम नलवा में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित थे।

लिव इन पार्टनर की हत्या, प्राइवेट पार्ट जलाया

धामनोद (नप्र)। धार पुलिस ने धामनोद में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। महिला को लिव इन पार्टनर ने ही मौत के घाट उतारा था। उसने महिला को किसी और के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

9 दिसंबर 2025 को धामनोद के पुराने रैदास मोहल्ले में सुनीता उर्फ कुंता का शव मिला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शुक्रवार को आई पोस्टमॉर्ट्म रिपोर्ट में उसकी बॉडी पर मारपीट, जलने के निशान और प्राइवेट पार्ट पर सूजन पाई गई। उसके हाथ-पैर भी मुड़े हुए थे, जिससे महिला के साथ क्रूरता करने की बात स्पष्ट हो गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि सुनीता पिछले कई वर्षों से अपने पति से अलग होकर अजय उर्फ रवि चौहान के साथ लिव इन में रह रही थी। अजय बड़वाह के सिरसा का रहने वाला है।

दक्षिण अंडमान में

संघ प्रमुख भागवत और अमित शाह ने सावरकर की प्रतिमा का किया अनावरण

श्री विजयपुरम (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बेओडनाबाद में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण

किया। यह प्रतिमा दक्षिण अंडमान जिले के एक पार्क में स्थापित की गई है। शाह और भागवत ने पार्क परिसर में रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए। इसके बाद शाह और भागवत बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री विजया पुरम पहुंचे, जहां सावरकर पर आधारित एक गीत जारी किया।

पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे पाकिस्तानी पीएम

- रूसी राष्ट्रपति ने 40 मिनट इंतजार कराया था

मॉस्को (एजेंसी)। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में जबरन घुस गए। इस दौरान पुतिन तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ मीटिंग कर रहे थे। यह मामला तुर्कमेनिस्तान का है। यहां इंटरनेशनल पीस

एंड ट्रस्ट फोरम की मीटिंग हो रही है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन और पीएम शहबाज के बीच मीटिंग होनी थी। लेकिन शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार कराने के बाद भी पुतिन उनसे मिलने नहीं पहुंचे। इसके बाद शहबाज थककर वहां से निकल गए और पुतिन-एर्दोगन की चल रही मीटिंग में शामिल होने चले गए।

हिमाचल में जमने लगा बहता पानी

- मैदानी इलाकों में कोहरे से बढ़ी ठंड, 8 शहरों में पारा 3 डिग्री से नीचे गिरा, 13-14 को बारिश-बर्फबारी

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहता पानी जमने लगा है। खासकर लाहौल घाटी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बिलासपुर और मंडी में आज सुबह के वक्त भी विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे गिर गई। सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना के निचले इलाकों में भी सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा। मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से निरंतर ठंड बढ़ रही है। इसके विपरीत, ठंडे शहर शिमला, कुफरी और नारकंडा में रात के तापमान में उछाल आया है। शिमला का न्यूनतम तापमान नॉर्मल से 3.5 डिग्री के उछाल के साथ 9.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जबकि मैदानी इलाकों में तापमान जमाव बिंदू के आसपास पहुंच गया है।

मप्र में पचमढ़ी से भी ठंडा इंदौर, पारा 5 डिग्री से नीचे

मध्य प्रदेश में लगातार तापमान गिर रहा है। इससे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इंदौर में राज्य के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। यहां

गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह पिछले 10 साल में सबसे कम तापमान है। वहीं, पचमढ़ी में पारा 4.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर सहित 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

तमिलनाडु में स्टालिन की राह मुश्किल?

- अचानक टीवीके ऑफिस पहुंचे पीएमके के कद्दावर नेता

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल बढ़ गई है। पीएमके नेता डॉ अंबुमणी रामदॉस की टीम के अगम सदस्य के. बालू ने अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के दफ्तर पहुंचकर सबको चौंका दिया।इस मुलाकात से दोनों दलों के संभावित

गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है।बालू ने बताया कि उनकी इस मुलाकात का मकसद टीवीके को 17 दिसंबर को चेन्नई में होने वाले पीएमके के प्रदर्शन में बुलाना था। यह प्रदर्शन राज्य में जाति आधारित सर्वे कराने की मांग को लेकर होगा। गठबंधन के सवाल पर बालू ने कहा, यह सिर्फ प्रदर्शन को लेकर है। आगे क्या होगा कौन जानता है?

पाइपलाइन फूटने से 30 फीट ऊंचा उठा फव्वारा

खेतों में घुसा पानी, किसान की 5 एकड़ चने की फसल हुई नष्ट

खरगोन (नप्र)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सेगांव क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया। इससे हड़कंप मच गया। जिले के नांगलवाड़ी उद्वहन नर्मदा परियोजना की मेन पाइपलाइन धमाके के साथ फट गई। घटना स्कूल के नजदीक हुई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हालांकि किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

मिली जानकारी के अनुसार, शाम करीब 5 बजे जमोठी गांव के पास अचानक नर्मदा पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद तेज दबाव के कारण पानी का विशाल फव्वारा आसमान में उठने लगा। कुछ ही मिनटों में पानी आसपास के खेतों और नजदीकी सरकारी माध्यमिक विद्यालय में घुस गया।

स्कूल से 50 मीटर दूर हुआ धमाका- गनीमत रही कि पाइप फटने से लगभग 30 मिनट पहले ही स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे घर लौट चुके थे। घटना के समय विद्यालय परिसर खाली होने से किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

किसान की 5 एकड़ फसल हुई नष्ट- हादसे में जनहानि तो नहीं हुई लेकिन तेज बहाव के कारण किसान जगदीश मंडलोई की लगभग 5 एकड़ चने की फसल पूरी तरह बह गई। ग्रामीणों के अनुसार पाइपलाइन में लंबे समय से लीकेज की समस्या बनी हुई थी। लेकिन, विभाग द्वारा समय पर मरम्मत नहीं की गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक केदार डावर और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडलोई मौके पर पहुंचे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से चर्चा की और तत्काल प्रभाव से नुकसान का आंकलन करवाने के निर्देश दिए।

सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाए : राहुल गांधी

- रिजिजू बोले- हम संसद में चर्चा को तैयार; अनुराग ठाकुर बोले- तमिलनाडु सरकार सनातन धर्म विरोधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं।

राहुल ने कहा, यह एक अहम मुद्दा है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार और हमारे बीच इस मामले पर एक सहमति होगी। इस सदन में मौजूद हर सदस्य इस बात से सहमत होगा कि प्रदूषण के कारण देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है, उस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे।

इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

राहुल ने कांग्रेस सांसदों से संसद में पार्टी परफॉर्मेंस पर चर्चा की

राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। इसमें संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा हुई।कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

कांग्रेस सांसदों की बैठक में शशि थरूर नहीं पहुंचे- सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राहुल ने शुक्रवार को संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। इसमें शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा हुई। हालांकि, केरल से पार्टी के सांसद शशि थरूर बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले 30 नवंबर को कांग्रेस की एक स्ट्रैटजिक मीटिंग में भी थरूर शामिल नहीं हुए थे। तब थरूर ने अपनी सफाई में कहा था कि वे अपनी 90 साल की मां के साथ फ्लाइट में थे। इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाए।

लखनऊ में बर्खास्त एसटीएफ सिपाही की कोठी पर ईडी की रेड

- सरगना शुभम और राणा बंधु के घर भी खंगाल रही

लखनऊ (एजेंसी)। कफ सिरप तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह बड़ा एक्शन लिया। लखनऊ, रांची और अहमदाबाद समेत देशभर में सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ में सुबह 6 बजे 8 सदस्यीय टीम एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह की आलीशान कोठी पर पहुंची और तलाशी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, कोठी से कई संदिग्ध दस्तावेज, बैंक लेन-देन से जुड़ी फाइलें, डिजिटल डिवाइस और कथित हवाला एंट्रीज से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं।

राजस्थान में गैंगवार, हिस्ट्रीशीटर समेत 2 की मौत

- 3 किलोमीटर दूर तक एक-दूसरे पर गोलियां चलाते रहे, भीड़ ने 2 बदमाशों को पकड़कर पीटा

जयपुर (झुंझुनूं) (एजेंसी)। राजस्थान के झुंझुनूं में हुई गैंगवार में हिस्ट्रीशीटर समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई। गैंगवार नवलगढ़ के गोठड़ा थाना क्षेत्र के खिरोड़ की शुक्रवार सुबह 9 बजे है। भीड़ ने दो बदमाशों को पकड़कर पीट दिया।

पुलिस ने बताया गैंगवार में हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी और सुनिल सुंडा की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कहा- शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे रविंद्र कटेवा (गोठड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर) कैमरी की ढाणी स्थित अपने मकान पर था। सुनील सुंडा निवासी ढाका की ढाणी भी रविंद्र के साथ था। इस दौरान मकान में एक स्विफ्ट कार आकर रुकी।

नीचे झुककर रविंद्र कटेवा ने बचाई जान- कार में रानोली थाने का पलसाना निवासी हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी अपने तीन और साथियों के साथ पहुंचा। उसने आते ही हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा पर फायरिंग की। रविंद्र कटेवा नीचे झुक गया और बच गया। फायरिंग के बाद कृष्णकांत और उसके साथी मौके से भागने लगे और गाड़ी में बैठ गए।

सुनील ने पकड़ा तो गोली मारी- इसी दौरान सुनील सुंडा ने कृष्णकांत की गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़ लिया और उसे भागने से रोकने लगा। कृष्णकांत और उसके साथियों ने सनील पर फायरिंग कर डाली।

छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश-बॉर्डर पर घाटी से गिरी बस, 9 यात्रियों की मौत

जगदलपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित मारेडमिल्ली घाटी पर एक यात्री बस पलट गई है। हादसे में 9 यात्रियों की ऑन स्पॉट मौत हो गई है, जबकि कुछ यात्री घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। मामला मारेडमिल्ली थाना क्षेत्र का है। हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे।

घटनास्थल के वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें दिखा कि बस घाटी से गिरकर नीचे घनी झाड़ियों में फंस गई। कई यात्री बस से नीचे सड़क पर गिर गए। सड़क पर मृतकों के शव और लोगों का सामान बिखरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि, 12 दिसंबर की सुबह बस अरकू से रायलासीमा चिंतुर जा रही थी। इसमें करीब 40 यात्री सवार थे। इसी बीच घाट में बस अनियंत्रित हुई और नीचे गिर गई।

नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ीं

- रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71 प्रतिशत पर पहुंची, अक्टूबर में ये 0.25 प्रतिशत पर थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में ये 0.25 प्रतिशत पर थी, जो 14 साल में सबसे कम स्तर रहा था। नवंबर महीने में महंगाई में बढ़ोतरी सब्जियों, अंडे, मांस-मछली, मसालों, फ्यूल और लाइट की कीमतें बढ़ने की वजह से हुई है। सरकार ने शुक्रवार, 12 दिसंबर को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं।

विदेश से लड़की को ब्याह लाया इंदौर का लड़का, हिंदू रीति से पाणिग्रहण

दस साल इंतजार किया, फिर ऐसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा

इंदौर। पिछले दिनों शहर में एक इंटरनेशनल लव मैरिज हुई। महू का दूल्हा अपने लिए थाईलैंड से दुल्हन ढूंढ लाया और इसी के साथ लव अफेयर शादी में बदल गया। लेकिन, इस कोशिश में दूल्हे को 10 साल लग गए। प्यार की यह कहानी बेहद दिलचस्प है। क्योंकि, प्यार को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। जिसके लिए दिल में प्यार आ जाए, वह उसे अपना मान लेता है। तकनीक भरे जमाने में भला सरहद में प्यार को कैसे बांध सकते हैं। दोनों की मुलाकात 2015 में हुई, 2018 में रिश्ते के लिए प्रपोज किया, तब 2025 में थाईलैंड की नारू एपक भारतीय बहू बनी।

महू के रहने वाले जयंत सोनी से नारू एपक उर्फ़ नैन की शादी हुई। विवाह हिंदू रीति रिवाज, बैंड बाजे और पारंपरिक भारतीय दुल्हन के लिबास में हुआ। अब ससुराल में नारू एपक नैन बन गई। नैन हिंदी नहीं जानतीं, वह अंग्रेजी में ही बात करती हैं। कई सालों से जयंत सोनी थाईलैंड के फुकेट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात नैन से हुई। शुरुआत में वह जयंत की कंपनी में उनकी असिस्टेंट थीं। काम से शुरू हुई यह मुलाकात धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। करीब दस साल तक दोनों ने साथ काम किया और मुसीबत के दौरान एक-दूसरे की मदद की। इससे एक-दूसरे के प्रति समझदारी और सम्मान ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया। 2018 में जयंत ने नैन को प्रपोज किया। पर, रिश्ते को नाम मिलने में 7 साल लग गए। इस दौरान नैन ने भारतीय परंपराओं और संस्कृति को करीब से महसूस किया और सोनी परिवार ने भी उन्हें खुले दिल से अपनाया। विवाह में थाईलैंड से नैन के माता-पिता और करीबी दोस्त भी महू पहुंचे। लाल जोड़े और खूबसूरत भारतीय लहंगे में सजी नैन ने हाथों में मेहंदी लगाई। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर के साथ नैन भारतीय दुल्हन ही लग रही थीं। भारत की बहू बनकर नैन को खुशी है। हिंदू रीति रिवाज से शादी करना बहुत अच्छा लगा। लोगों के व्यवहार और प्यार ने उनका दिल जीत लिया। भाषा के सवाल पर नैन ने कहा कि प्यार और आत्मीयता जहां होती है, वहां भाषा की दीवार खत्म हो जाती है। जयंत के बारे में नैन कहतीं हैं कि शुरुआत में जयंत को थोड़ा कठोर और गुस्सैल समझती थी। लेकिन, समय के साथ उन्हें पता चला कि जयंत दिल के बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। जयंत ने एक बार नैन को अपनी बहन की शादी में भारत बुलाया था। वह नैन की पहली भारत यात्रा थी। उस यात्रा से ही उनकी जिंदगी बदल गई।

प्रेम प्रसंग में धोखा मिला तो फांसी लगाई

इंदौर। पांच दिन पहले भोपाल से लौटे युवक ने घर आने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय दादी दवाई लेने गई थी, घर पर कोई नहीं था। परदेशीपुरा पुलिस के अनुसार मृतक का नाम मोहित तरवरिया निवासी कुलकर्णी भट्ट है। वह पांच दिन बाद बुधवार सुबह ही भोपाल से लौटा था और शाम को आत्महत्या कर ली। मोहित का भाई शुभम जब घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर आवाज देने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो शुभम ने अंदर झांककर देखा। तब मोहित फंदे पर लटका दिखाई दिया। शुभम ने बताया कि मोहित ने भोपाल में एक मेले में बुक स्टॉल लगाया था। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसलिए आत्महत्या के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि मोबाइल जब्त कर लिया है, जिसकी जांच की जाएगी। शुभम ने बताया कि मोहित का एक साल से कशिश नाम की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों में काफी बातें होती थीं, मोहित उसे लेकर सीरियस था।

बाइक सवार को लूटने की कोशिश

इंदौर। एरोड्रम इलाके में बुधवार रात एक युवक के साथ लूट की कोशिश का मामला सामने आया। स्पोर्ट्स बाइक पर सवार दो बदमाशों ने चलते वाहन पर युवक को थप्पड़ मारा और रुकवाने की कोशिश की। युवक के विरोध करने पर उन्होंने उसकी शर्ट तक खींच ली और धमकाते हुए भाग गए। एरोड्रम पुलिस ने पीड़ित आदित्य खतवाशे निवासी नंदन नगर की शिकायत पर बाइक (एमपी 09 एक्यू 5079) पर सवार दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आदित्य ने पुलिस को बताया कि वह सिटी स्कूल के पास, कालका माता मंदिर रोड से गुजर रहा था। तभी सामने से आई स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे दो युवकों में से एक ने अचानक उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। वह किसी तरह संभला तो बदमाशों ने उसकी बाइक रोकने की कोशिश की और शर्ट पकड़कर खींचा, जिससे उसकी जेब फट गई। आदित्य के चिल्लाने पर दोनों आरोपी धमकी देते हुए वहां से भाग गए। पुलिस अब आस-पास के सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।

आजाद नगर और पलासिया में चाकूबाजी

इंदौर। आजाद नगर और पलासिया थाना क्षेत्र में दो जगह चाकूबाजी में युवक घायल हो गए। मामले में पुलिस ने आटो चालक सहित चार बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया है। आशीष कुशवाह ने पलासिया पुलिस को बताया कि वह रात करीब 10.30 बजे गीता भवन चौराहे पर दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी दौरान, आटो रिक्शा में बैठे चार युवकों ने उन्हें और उनके साथी को देखकर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। फिर चारों युवक आटो से उतरकर झगड़ा करने लगे। विवाद बढ़ने पर, आटो चालक ने मुझे बाईं जांघ पर चाकू मार दिया। पुलिस ने ऑटो चालक सहित चार अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आजाद नगर इलाके में विवाद में आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना कोहिनूर कॉलोनी में हुई। घायल का नाम मोईन पिता उस्मान खान निवासी प्रेम नगर है। रिपोर्ट पर आरोपी हुमायूं उर्फ भय्यू, कालू और आफताब निवासी मीना पैलेस आजाद नगर के खिलाफ केस दर्ज किया। फरियादी ने बताया कि विवाद की बात को लेकर शाम करीब 7.30 बजे आरोपी आए और गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो चाकू से वार किया।

लाखों के जेवर और नकदी चुराई

इंदौर। गांधीनगर के समीप सतपुड़ा परिसर में चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाते हुए वहां से लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बड़ा बांगड़दा रोड स्थित सतपुड़ा परिसर में रहने वाले सुनील शैन्द्रे ने बताया कि जब वे बुधवार शाम को अपने घर लौटे, तब उन्हें घटना का पता चला। किसी अज्ञात बदमाश ने उनके घर का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने कमरे में रखी अलमारी से सोने-चांदी के पुराने आभूषण चुरा लिए। चोरी की कुल कीमत का आकलन किया जा रहा है। गांधी नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अब चोरों का पता लगाने के लिए सतपुड़ा परिसर और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। बता दें, यह परिसर पूरी तरह से बाउंड्रीवाल से कवर है। मेन रोड पर होने से दिनभर पुलिस की भी आवाजाही बनी रहती है, इसके बावजूद वारदात होना आश्चर्य की बात है।

राजेन्द्र नगर में गर्भवती महिला से मारपीट

इंदौर। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आठ महीने की गर्भवती महिला की शिकायत पर उसके पति और सास के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है। अमर पैलेस कॉलोनी निवासी मुस्कान गायकवाड़ ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया। बहस बढ़ने पर पति अरुण राणे ने उसके पेट में लात मारी, जिससे उसे तेज दर्द होने लगा। इसी दौरान सास सोनू राणे ने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा।मुस्कान ने बताया कि कुछ दिन पहले 4 दिसंबर को नौकरी पर जाते समय भी पति से विवाद हुआ था और उस दिन भी उसने उसके साथ मारपीट की थी। वह रोजाना गाली-गलौज करता है। दर्द बढ़ने पर मुस्कान ने अपनी दादी मंगीबाई को फोन किया। दादी तुरंत आईं और उसे डॉक्टर के पास ले गईं। इलाज के बाद मुस्कान ने पति और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। डेढ़ साल पहले मुस्कान और अरुण ने कोर्ट मैरिज की थी।

नाचने के दौरान विवाद और मारपीट

इंदौर। जवाहर टेकरी पर नाचने के दौरान हुए विवाद में आरोपियों ने युवक की जमकर पिटाई की। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक, घायल युवक की पहचान हिमांशु पिता ईश्वर प्रजापत निवासी खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास सिरपुर के रूप में हुई है। मामले में आरोपी विजय, रूपेश, भोला और जितेंद्र सभी निवासी जवाहर टेकरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हिमांशु ने बताया कि वह 9 दिसंबर को रात 9.30 बजे अपने दोस्त की शादी के कार्यक्रम में जवाहर टेकरी गया था। बरात में दो डीजे गाड़ियां चल रही थीं। हिमांशु अपने दोस्त लक्की चौहान के साथ पीछे वाली गाड़ी के पास नाच रहे थे। नाचते-नाचते जब वे आगे वाली डीजे गाड़ी के पास पहुंचे तो हिमांशु का धक्का गलती से विजय को लग गया। इसी बात को लेकर विजय, रूपेश और भोला ने मारपीट कर दी।

अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

इंदौर। अवैध निर्माण रोकने गुरुवार को झोन 1 और 11 के पार्षदगण और विभागीय अधिकारी के साथ भवन अनुज्ञा शाखा में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के प्रभारी उदावत ने अवैध और अनाधिकृत निमार्णों पर गंभीर चिंता जताते हुए अधिकारियों को तुरंत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा दी गई शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण में बाधा डालने वाले निर्माण, उद्यान और बैकलेन में चल रहे अवैध निमार्णों की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण, सीएम हेल्पलाइन और मेयर हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी ने बताया कि भवन अनुज्ञा शाखा के प्रत्येक झोन में अलग-अलग बैठकें होगी, जिसमें संबंधित वार्डों के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत निर्माण संबंधी मुद्दों और आवश्यक कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

फ्लाइट कैंसिल हुई, तो बेटे की परीक्षा के लिए पिता ने 800 किमी कार चलाई

रेल में सीट नहीं मिली, तब इंदौर आने का विकल्प कार ही बचा

इंदौर। बीते एक सप्ताह में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से हजारों यात्री परेशान हुए। रोहतक का एक परिवार भी परेशानी में आ गया। इंडिगों की फ्लाइट कैंसिल होने से इंदौर आने की कोई सुविधा न देखकर पिता ने बेटे के लिए रातभर में 800 किमी कार चलाई। क्योंकि, बेटे की प्री-बोर्ड थी, इसलिए 800 किलोमीटर का सफर तय किया और सुबह तक समय पर इंदौर पहुंच गए। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने का असर देशभर में हजारों यात्रियों पर पड़ा। हरियाणा में रोहतक जिले के मायना गांव के पंघाल परिवार को भी इस स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ा।

फ्लाइट रद्द होने के बाद जो फैसला इस परिवार ने लिया, वह जिम्मेदारी, समर्पण और पिता-पुत्र के रिश्ते की मिसाल बन गया। मायना गांव के युवा अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज आशीष चौधरी पंघाल इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। इन दिनों वे परीक्षा से पहले कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आए थे। डेली कॉलेज में 6 दिसंबर की शाम को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आशीष को सम्मानित किया जाना था। इसके अलावा उनकी प्री-बोर्ड परीक्षा 8 दिसंबर से शुरू होनी थी।

दोनों ही कार्यक्रमों में समय पर पहुंचने के लिए दिल्ली से इंदौर की इंडिगो फ्लाइट पहले से बुक थी। 6 दिसंबर को आशीष के पिता खेल प्रेरक एवं अधिवक्ता राजनारायण पंघाल उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे। परिवार पूरी तैयारी के साथ एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन यहां उन्हें निराशा हाथ लगी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर पता चला कि इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक कैंसिल कर दी गई। यह खबर सुनते ही परिवार की चिंता बढ़ गई। फ्लाइट रद्द होने का मतलब था कि न केवल आशीष सम्मान समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, बल्कि 8 दिसंबर से शुरू होने वाली उनकी प्री-बोर्ड परीक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन में तत्काल सीट कंफर्म करवाने की कोशिश भी की गई। लेकिन, इंदौर के लिए सीट मिलना मुश्किल था। इस स्थिति में पिता राजनारायण पंघाल ने बिना देर किए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि चाहे फ्लाइट रद्द हो गई हो और ट्रेन में भी सीट न मिले, लेकिन वे बेटे को हर हाल में समय पर इंदौर पहुंचाएंगे। दिल्ली से इंदौर की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। इस सफर को तय करने में आमतौर पर 12 से 14 घंटे लगते हैं। लेकिन, पिता के इरादे मजबूत थे और उन्होंने उसी शाम कार स्टार्ट की और रात भर लगातार ड्राइव करते रहे। मुश्किलों और थकान को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने लंबी दूरी की ड्राइव की, ताकि बेटे की परीक्षा न छूटे। अगली सुबह वे आशीष के साथ समय पर इंदौर पहुंच गए। राजनारायण पंघाल ने कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने की खबर ने हमें हिला दिया था। परीक्षा बच्चे के भविष्य से जुड़ी चीज है, इसलिए मैंने तय किया कि चाहे रात भर ड्राइव करनी पड़े, लेकिन बेटे को समय पर पहुंचाना है। आखिरकार हम समय पर इंदौर पहुंच गए, यही सबसे बड़ी खुशी है।

यूरिया खाद के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगाने को किसान त्रस्त

सुधार नहीं हुआ तो किसानों की आंदोलन की चेतावनी

इंदौर। जिले में यूरिया खाद वितरण की अव्यवस्थित व्यवस्था एक बार फिर किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। हालात इतने बिगड़ गए कि लक्ष्मी नगर अनाज मंडी गोदाम के बाहर तड़के 5 बजे से ही किसान लाइन में खड़े दिखाई दिए। सुबह 6 बजे तक संख्या 100 से अधिक हो गई। कई किसान तो रात खुलते ही सुबह 4 बजे पहुंचकर अपने कागज रखकर लाइन में जगह सुरक्षित करने को मजबूर हुए। यह स्थिति मुख्यमंत्री के प्रभार वाले जिले में प्रशासनिक लापरवाही की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती है। किसान नेता बबलू जाधव ने बताया कि स्थानीय सोसायटियों में नगद भुगतान पर डिफाल्टर किसानों को भी खाद उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। उनका कहना है कि मार्कफेड के गोदाम गांवों से काफी दूर हैं, जिससे किसानों को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। समय, श्रम और पैसे का नुकसान अलग से हो रहा है। ऊपर से पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने से किसानों की चिंता और बढ़ रही है। जाधव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वितरण व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया और किसानों को गांव की सोसायटियों पर ही सहज रूप से खाद उपलब्ध नहीं करवाई गई, तो किसान बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। किसानों का कहना है कि यह केवल अव्यवस्था नहीं, बल्कि उनके साथ सीधा अन्याय है।

शहर के 14 शातिर बदमाशों पर सख्त कार्रवाई, पांच जिला बदर

शर्तों के साथ 9 बदमाशों पर थाना हाजिरी की पाबंदी

इंदौर। शहर में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने 14 सक्रिय और आदतन अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की। इनमें 5 कुख्यात बदमाशों को 6 माह के लिए इंदौर जिले और इससे लगे सीमावर्ती जिलों से जिलाबदर कर दिया। अन्य 9 बदमाशों को विभिन्न शर्तों के साथ थाना हाजिरी के आदेश जारी किए गए।

जिला बदर बदमाशों में आरिफ उर्फ काट डालू बेग, दिलीप बकावले, राजा उर्फ कचोरी श्रीवास, कान्हा उर्फ मोहित जरिया तथा रोहन उर्फ पॉपकॉर्न कदम शामिल है। इन सभी पर शहर के विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी इनके अपराध जारी रहने पर यह कठोर कदम उठाया गया। जबकि, बदमाश गोलू उर्फ गुलरेज को 1 वर्ष, रोहित उर्फ कालू को 1 वर्ष, सागर उर्फ छोटू को 1 वर्ष, मोहक उर्फ मोनू को 1 वर्ष, गोलू उर्फ अकबर को 6 माह, गब्बर उर्फ राजेश चिकना को 6 माह, लाल उर्फ रंजन को 6 माह, विजय उर्फ राजू को 6 माह तथा अजीजुद्दीन को 6 माह तक थाना हाजिरी के आदेश दिए हैं। निर्बन्धन के दौरान बदमाशों को निर्धारित समय पर संबंधित थाने में हाजिरी देना होगी। किसी भी अवैध गतिविधि से दूर रहना होगा।

शहर की शांति व्यवस्था भंग करने जैसा कोई कार्य नहीं करना होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी मामलों में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अजय प्रताप सिंह बुंदेला ने की।

ट्रांसमिशन लाइनों में चाइनीज मांझा फंसने से तेरह बार बिजली बाधित

चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वाले, अन्य को खतरे की आशंका

इंदौर। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने इंदौर शहर में ट्रांसमिशन लाइनों के नजदीक चायनीज मांझे से पतंग उड़ाने के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित दुर्घटनाओं और विद्युत व्यवधानों पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सतर्क व सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कंपनी अब इंदौर में एक विशेष 'रोको-टोको' अभियान चलाएगी। एमपी ट्रांसको की कार्यपालन अभियंता नम्रता जैन ने बताया कि पिछले दो सालों में इंदौर क्षेत्र में 13 बार ऐसी घटनाएं हुई, जब पतंगों के साथ चायनीज मांझा ट्रांसमिशन लाइनों के संपर्क में आया, जिससे न केवल बिजली आपूर्ति बाधित हुई, बल्कि ट्रांसमिशन लाइन क्षतिग्रस्त हुई। इस अभियान के तहत, एमपी ट्रांसको ने इंदौर के उन क्षेत्रों को चिह्नित किया है। जहां बहुतायत में पतंग उड़ाई जाती हैं। इन संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, बैनर और पीए सिस्टम के माध्यम से भी लोगों को सचेत और सतर्क किया जाएगा, ताकि जान-माल की हानि रोकी जा सके और उपभोक्ताओं को व्यापक क्षेत्र में बिजली के अनावश्यक लंबे व्यवधान का सामना न करना पड़े।

इसलिए घातक चाइनीज मांझा- चायनीज मांझा, जो कि सामान्य सूती धागे से अलग होता है, विद्युत का सुचालक होने के कारण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रांसमिशन लाइनों के संपर्क में आने पर यह न केवल बिजली आपूर्ति में व्यवधान डालता है, बल्कि जान-माल की हानि का कारण भी बन सकता है। जब यह मांझा बिजली के तारों से टकराता है, तो इसमें मौजूद सामग्री के कारण करंट प्रवाहित हो सकता है, जिससे पतंग उड़ाने वाले और आसपास के लोगों को गंभीर खतरा होता है।

ये क्षेत्र है संवेदनशील

इंदौर में जिन क्षेत्रों को चायनीज मांझा के साथ पतंग उड़ाने के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है, उनमें मुख्य रूप से लिम्बोदी, मूसाखेड़ी, खजराना, महालक्ष्मी नगर, सुखलिया, गौरीनगर, बाणगंगा, तेजाजी नगर और नेमावर रोड शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अभियान पर विशेष जोर रहेगा।

राजा हत्याकांड में सोनम की दो दोस्तों की शिलांग कोर्ट में पेशी

सोनम के व्यवहार पर पूछताछ, एक सहेली के बयान हुए

इंदौर। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की दो सहेलियां दीपांशी और प्रियांशी की गुरुवार को शिलांग कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुईं। दोनों युवतियां इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुईं। कोर्ट में उनकी कानूनी टीम भी मौजूद रही। दोनों सहेलियां सोनम के भाई गोविंद की फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करती हैं। वे ई-सेवा प्लेटफार्म के माध्यम से सुनवाई से जुड़ीं। कोर्ट ने सबसे पहले दीपांशु से सोनम की पहचान कराई। फिर उससे पूछा गया कि सोनम का व्यवहार कैसा रहता था? यह सवाल भी किया गया कि क्या वह राजा रघुवंशी को जानती थी? कोर्ट ने दीपांशु का बयान दर्ज कर लिया, जबकि प्रियांशी का बयान अगली पेशी में लिया जाएगा। बयान देने के बाद दोनों बिना मीडिया से बात किए कोर्ट से निकल गईं। दीपांशी और प्रियांशी की पेशी के लिए सरकारी वकील ने कोर्ट से मांग की थी। उन्हें इसका नोटिस 27 नवंबर 2025 को मिला था। यह सरकारी वकील का दूसरा नोटिस था। पहले नोटिस पर दोनों शिलॉन्ग में उपस्थित नहीं हुई थीं।

कैसे हुआ था मामला- राजा रघुवंशी और सोनम की 11 मई को शादी हुई थी। दोनों 20 मई को हनीमून के लिए

मेघालय गए और 22 मई को सोहरा घूमने निकले थे। इसी दौरान दोनों लापता हो गए। 24 मई से परिवार का संपर्क टूट गया। 27 मई से सर्चिंग शुरू हुई। 2 जून को गहरी खाई में राजा का शव मिला था। शव की पहचान राजा के भाई विपिन ने की थी। जांच के बाद पुलिस ने सोनम सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया था। पूछताछ के बाद तीन अन्य को साक्ष्य मिटाने के मामले में गिरफ्तार किया था। पोस्टमॉर्टम में पता चला कि उसकी हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी।

ऐसे पकड़ी गई सोनम

राजा की मौत के बाद पुलिस ने सोनम की तलाश शुरू की और वह 9 जून को यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। अब तक इस केस में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 को जमानत मिल चुकी है।

निजामुद्दीन-बांद्रा, डॉ. अंबेडकर नगर-तोकुर के बीच स्पेशल ट्रेन

त्योहारी सीजन में यात्रियों को दो ट्रेनों से सौगात मिलेगी

इंदौर। त्योहार, शीतकालीन अवकाश और बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की। इनमें पहली ट्रेन निजामुद्दीन-बांद्रा टर्मिनस एसी स्पेशल है, जो रतलाम मंडल में ठहराव के साथ एक-एक फेरा चलेगी। दूसरी डॉ अंबेडकर नगर-तोकुर स्पेशल ट्रेन है, जो विशेष किराए पर दो-दो फेरों में संचालित होगी।

निजामुद्दीन-बांद्रा एसी स्पेशल - इस ट्रेन से लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। गाड़ी संख्या 04006 गुरुवार 11 दिसंबर को निजामुद्दीन से रवाना होकर 12 दिसंबर शुक्रवार को 11.00 बजे बांद्रा पहुंचेगी। रतलाम में इसका आगमन 00.30 बजे और प्रस्थान 00.40 बजे हुआ। वहीं वापसी में 04005 बांद्रा से 12 दिसंबर को 14.40 बजे चलेगी और 13 दिसंबर को 11.10 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। इस फुल एसी स्पेशल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी कोच शामिल हैं तथा कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत और बोरीवली में स्टॉपेज रहेगा।

अंबेडकर नगर-तोकुर स्पेशल- इस स्पेशल ट्रेन से छुट्टियों में भीड़ का समाधान होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी (संख्या 09304/09303) दो फेरों में चलाई जाएगी। 09304 अंबेडकर नगर से 21 व 28 दिसंबर को शाम 4.30 बजे चलेगी और मंगलवार सुबह 3.00 बजे तोकुर पहुंचेगी। इस दौरान इंदौर, देवास, उज्जैन, नागदा और रतलाम सहित कई स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। वापसी में 09303 ट्रेन 23 व 30 दिसंबर को सुबह 5.00 बजे तोकुर से चलकर अगले दिन दोपहर 3.30 बजे अंबेडकर नगर पहुंचेगी। यह ट्रेन पूर्णतः आरक्षित है, जिसमें थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगाए जाएंगे।

टिकट बुकिंग 13 दिसंबर से- 09304 के लिए टिकट आरक्षण 13 दिसंबर 2025 से यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पूर्व समय-सारणी एवं संबंधित अपडेट भारतीय रेल की आधिकारिक जानकारी स्रोतों से प्राप्त करें।

संपादकीय

सीएम यादव : उपलब्धियों भरे दो साल!

दो साल पहले जब डॉ. मोहन यादव को मध्यप्रदेश की कमान सौंपने का फैसला भाजपा आलाकमान ने किया तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पूर्व में लगभग 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज खास शैली में ढले प्रशासन की चाल-ढाल बदलने, अपना एक अलग विजन, प्रभावी और जनोन्मुखी कार्य शैली गढ़ने की चुनौती थी। मोहन यादव इन कसौटियों पर काफी हद तक खरे उतरे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दो साल का कार्यकाल सुशासन की नई परिभाषा गढ़ने, सरकार को विकासोन्मुखी तथा लोकहितकारी बनाने के बहुआयामी प्रयासों से परिपूर्ण है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का विजन भी वही है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र का मोदी का है। यानी आजादी की सौंवी वर्षगांठ 2047 तक मप्र को देश के विकसित और प्रगत राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा करना। इसी तारतम्य में सीएम ने अफसरों को साफ कह दिया है कि वे विजन 2047 के तहत पहले पांच वर्ष का रोडमैप तैयार कर उस पर गंभीरता से काम करें। इस 'डबल इंजन के विजन' में कहीं कोई दरार नहीं है। इसी के मद्देनजर मोहन यादव सरकार ने पिछले साल गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से चार मिशन लांच किए। आगामी लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक मप्र की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर की बनाया जाए साथ ही 2029 तक राज्य की जीएसडीपी दोगुनी की जाए। सीएम यादव का सपना मप्र को देश की मिल्क कैपिटल (दुग्ध राजधानी) बनाना है। निरपेक्ष भाव से देखें तो मोहन यादव सरकार ने विगत दो सालों में न केवल कई जनहितैषी निर्णय लिए हैं, प्रशासनिक मशीनरी को कसा है बल्कि कई पुराने फैसले जनहित में पलटे भी हैं। इससे जनता में सही संदेश गया है। खुद मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के शब्दों में कहें तो विगत दो वर्षों में मप्र ने प्रगति के नए आयाम गढ़े हैं। राज्य में दो साल में 8 लाख करोड़ रू. का पूंजी निवेश हुआ है और 6 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। कृषि, उद्योग, और शिक्षा के बाद मप्र अब धार्मिक पर्यटन और अध्यात्म के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। डॉ. मोहन यादव सरकार के दो साल का कार्यकाल मोटे तौर चार पैमानों पर आकलित किया जाना चाहिए। ये हैं- राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक। ये चारों पैमाने ही विकास के रथ के चार चक्र हैं। उल्लेखनीय है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी बहुमत से सत्ता में वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मप्र में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लेते समय यह भी ध्यान रखा था कि इसका संदेश दूर तक जाए। इसीलिए जब सीएम पद के लिए डॉ.मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई तो यह बहुतों को चौंकाने वाली थी। इसके पीछे न केवल उच्च शिक्षित मोहन यादव के रूप में अपेक्षाकृत युवा चेहरे को आगे बढ़ाना था बल्कि राष्ट्रीय संदर्भ में एक नया यादव नेतृत्व तैयार करना भी था। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सहमति थी। जो अपेक्षा थी और जो चुनौतियां थीं, डॉ. मोहन यादव अपनी शांत और संयमित कार्यशैली से उन पर काफी हद तक खरा उतरे हैं। मप्र को विकास का नया हब बनाना उनका लक्ष्य है। यह काम असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। सपनों को साकार करने के लिए एक समर्पित टीम का होना भी जरूरी है। इस मोर्चे पर डॉ. मोहन यादव की तैयारी कमजोर दिखाई पड़ती है, क्योंकि दो साल बाद भी उनकी अधिकारियों की कोर टीम नहीं बन पाई है। फिर भी आलाकमान के वरदहस्त ने उनकी कई मुश्किलों को आसान किया है।

एसआईआर पर बंगाल का दृश्य डरावना

नजरिया

अवधेश कुमार

लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

यूपी में भी संघ इसी रणनीति को लागू करने की तैयारी में है। विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए बीजेपी को राजनीतिक समझौते करने पड़ सकते हैं, जैसे कि बीएसपी से कथित सहयोग। यूपी में भी संघ और बीजेपी की रणनीति यही होगी कि हिंदू वोट को बांटे बिना संगठन और विकास के एजेंडे को मजबूत किया जाए। बीते हफ्तों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ आए और दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में भाग लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा किया और बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की। इसके अलावा, बीएल संतोष की संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक समन्वय पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर यानी विशेष मतदाता निरीक्षण अभियान चल रहा है। इनमें पश्चिम बंगाल का पूरा दृश्य भयभीत करने वाला है। जितनी बड़ी संख्या में वहां बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर या मतदान केंद्र स्तर कर्मियों की मृत्यु या आत्महत्या की बातें उठाई जा रही है वह अकल्पनीय है। पूरी तृणमूल कांग्रेस और स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के विरुद्ध आक्रामक मोर्चा खोल दिया है। ममता ने आयोग को औपचारिक रूप से दो पत्र लिखे जिनमें इसे अनियोजित तरीके से आरंभ कर लोगों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया तथा इसे तत्क्षण रोकने की भी मांग की। उनके पत्र में ऐसा न करने पर परिणाम के लिए उत्तरदायी होने की धमकी और चेतावनी दोनों थी। बंगाल पहला राज्य है जहां बीएलओ के बैनर से मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। 28 नवंबर को तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी बातें रखीं। आयोग के हवाले से समाचार आया कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से एस आई आर की प्रक्रिया में बाधा न डालने तथा दुष्प्रचार न करने का अनुरोध किया। आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राजनीतिक बयान आपका अधिकार है लेकिन दुष्प्रचार कर समस्याएं पैदा करना उचित नहीं है। आयोग ने बीएलओ की मृत्यु या आत्महत्या के आरोपों से भी इनकार किया। यद्यपि कुछ मामलों में जांच की भी बात की। निश्चय ही हमारे आपके अंदर एस आई आर की पूरी प्रक्रिया तथा उसकी तात्कालिक परिणतियों को लेकर अनेक प्रश्न और संदेह पैदा होंगे।

विचार करने की बात है की अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दृश्य ऐसे क्यों नहीं है? हमने बिहार एस आई आर के दौरान राजनीतिक नेताओं के तेवर देखें, राहुल गांधी की 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा हुई ,उच्चतम न्यायालय में नामी वकीलों ने इसके विरुद्ध बहस की किंतु प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। इस समय भी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि जब आप बिहार के बारे में बातें कर रहे थे तो हमें भी लगा कि कुछ गड़बड़ी हुई है और हमने वहां वॉलिंटियर्स नियुक्त किए? आपने कहा कि लाखों के नाम कट रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं आया जिसने अपना नाम काटने का आरोप लगाया। दूसरे, आपने कहा कि लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है जबकि दिखाई दिया कि गांव के स्तरों पर भी लोगों को पूरी जानकारी थी। इसी तरह की टिप्पणी अन्य न्यायाधीशों की भी आई है। आधार कार्ड पर भी न्यायालय ने प्रश्न किया कि किसी विदेशी नागरिक के पास आधार कार्ड है तो क्या उसे मतदान का अधिकार दे दिया जाएगा? स्पष्ट है कि एसआईआर की पूरी सुनवाई और मॉनिटरिंग के बाद उच्चतम न्यायालय किन सच्चाइयों पर पहुंचा है। एस आई आर की प्रक्रिया ऐसी जटिल नहीं है जिसके दबाव में या परेशान होकर बीएलओ को आत्महत्या करनी पड़ी या उसकी मृत्यु हो जाए। बिहार के अलावा अभी जिन राज्यों में हो रहे हैं वहां बी एल ओ लोगों को फोन करते हैं, पास जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के बीएलए बूथ लेवल एजेंट भी फोन करते हैं कि आपके पास फार्म पहुंचे नहीं पहुंचे आदि आदि और सहयोग से सारा काम चल रहा है। थोड़े बहुत परिश्रम के बाद कागजात भी हो जा रहा है।

किंतु बंगाल की स्थिति भिन्न है। न भूलिए कि वहां एनआईए आतंकवाद के मामले में कार्रवाई करने जाती है तो उन पर हमले होते हैं और कार्रवाई के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल लाना पड़ता है। बंगाल में एस आई आर की सूचना के साथ कुछ मोहल्ले खाली हो गए और पता चला कि सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों थे। बांग्लादेश की सीमा पर भीड़ दिखी जो बता रहे हैं किघुसपैठ कर आए, उनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बने और उन्होंने मतदान भी किया। टीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बीएसएफ से कह रहे हैं कि हमें उस ओर जाने दीजिए। बावजूद पूरी तृणमूल कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं की कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया उनके यहां हैं। उल्टे मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटने का ही आरोप लगा रहे। यह एक पहलू बताने के लिए पर्याप्त है कि बंगाल में बीएलओ के साथ क्या हो रहा होगा।

दो अन्य पहलू भी पर ध्यान दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर के दौरान कई राज्यों में विसंगतियां सामने आई है। मुंबई की मतदाता सूची में 10.64 प्रतिशत यानी 11 लाख से अधिक डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं। कुछ वार्डों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 से लेकर 103 बार तक मिला। बंगाल का मामला कहीं अधिक बड़ा है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची की तुलना पिछली एस आई आर (2002-2006) के रिकॉर्ड से करने पर लाखों नामों की विसंगति सामने आई। आयोग के पोर्टल पर गणना प्रपत्र अपलोड किए जाने के बाद मैपिंग प्रक्रिया में आते ही मिलान पुराने रिकॉर्ड से किया जाता है। मतदाता सूची में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मिसमैच चाहे वह मृत्यु रिकॉर्ड , निवास या पता बदलने , बाहर चले जाने या नाम के दोहरीकरण से हो चुनाव की पारदर्शिता को सीधे प्रभावित करने वाला पहलू है। बंगाल की सूची में 47 लाख ऐसे मतदाता सामने आये थे, जो अब दुनिया में नहीं हैं। इनमें 34 लाख ऐसे थे, जिनके आधार कार्ड भी बने थे।

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर कई शोध हुए हैं। अगस्त 2025 में प्रकाशित शोध इलेक्टरल रोल इन्फ्लेशन इन वेस्ट बेंगालः अ डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन औफ लेजिटीमेट वोटर काउंट्स (2024) में विद्यु शेखर (एसपी जैन, मुंबई) और मिलन कुमार (आईआईएम विशाखापत्तनम)-- के अनुसार, 2024 की मतदाता सूची में करीब 1.04 करोड़ अतिरिक्त नाम हैं। यह कुल नाम का लगभग 13.69 प्रतिशत है। वस्तुतः 2004 में राज्य में 4.74 करोड़ मतदाता थे। 1986 से 2006 के बीच जन्मे और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं को जोड़ने, प्रवासन, प्राकृतिक मृत्यु दर और उम्र के आधार पर अनुमान लगाया गया कि 2024 में पश्चिम बंगाल में वैध मतदाताओं की संख्या करीब 6.57 करोड़ होनी चाहिए थी, जबकि है, 7.61 करोड़। जन्म और मृत्यु दर बिल्कुल निश्चित है। उसके आधार पर कितने मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। इस आंकड़े में कुछ लाख का ऊपर नीचे हो सकता है। यह सब सच है तो फिर बीएलओ के सामने कैसी परिस्थितियों तृणमूल कांग्रेस या अन्य लोग उत्पन्न कर रहे होंगे इसकी कल्पना करिए। समाचार के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत में आयोग ने स्पष्ट कहा की वे मृत, स्थानांतरित और डुप्लिकेट मतदाताओं के संबंध में बीएलओ पर दबाव न डालें या धमकी नहीं दें। जब आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जिनके या जिनके परिवारों के नाम 2002 की मतदाता सूची में है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं तो असुरक्षा, आशंका और भय का माहौल क्यों? बिहार में भी नेताओं ने तनाव पैदा करने की कोशिश की लेकिन एक बीएलओ की मृत्यु नहीं हुई। बिहार में लगभग 68.66 लाख लोगों के नाम काटे और लगभग 21.53 लाख नए नाम मतदाता सूची में शामिल हुए। वहां एस आई आर आरंभ होने के पूर्व मतदाताओं की संख्या सात करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 थी जो घटकर 7.24 करोड़ से थोड़ा अधिक हो गई। पता चला कि इनमें 22 लाख 34 हजार 136 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी और कुल 36 लाख 44 हजार 939 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके थे। इसके अलावा छह लाख 85 हजार मतदाताओं के नाम दो या उससे ज्यादा जगह थे। सारे हंगामों केबावजूद केवल 36,475 मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए दावा पेश किया जबकि 2,17,049 मतदाताओं ने नाम हटाने के लिए आवेदन किए। मतदाता सूची जारी होने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने कहा हो कि उसकी कोशिशें के बावजूद नाम नहीं जोड़ा गया। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ ,राजस्थान, महाराष्ट्र सब जगह एस आई आर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रश्न उठाएं किंतु वहां भी इस तरह के दृश्य नहीं है। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रहा है ताकि दुनिया छोड़ गये या अन्यत्र चले जाने वालों के नाम हट जाए तथा कोई नाम एक ही जगह की सूची में हो। लंबे समय से मांग थी की अलग-अलग चुनावों के लिए अलग-अलग मतदाता सूचियां की जगह एक राष्ट्रीय स्तर की सूची हो। एस आई आर की प्रक्रिया के बाद भारत वह लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। बंगाल से आ रहे दृश्य बता रहे हैं कि सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह मतदाता सूची को दूषित किया हुआ है।

आपदा सुरक्षा ध्यान में रखकर हो शहरी विकास

भूकंप और हिमालय

श्रीराम माहेश्वरी

लेखक पर्यावरणविद हैं।

संतों के लिए हिमालय तपोभूमि और देवभूमि है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से हिमालय एक मजबूत ढाल है। जीवनदायी नदियों का मुख्य स्रोत यही हिमालय है, वही औषधीय निर्माण के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां इसी हिमालय से उपलब्ध होती हैं। मानव सभ्यता के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन हिमालय की ही देन है। इन सबके बावजूद पर्यावरण की दृष्टि से आज हिमालय पर संकट है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पर्यावरण और भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है।

हिमालय क्षेत्र का नया मूल्यांकन अध्ययन प्रकाश में आया है। इसमें बताया गया है कि भूकंपीय तनाव हिमालय के दक्षिण तक हिमालय फ्रंटल थ्रष्ट में फैल गया है। यानी भूकंप का जोखिम सिर्फ पहाड़ो तक सीमित नहीं है। इसका विस्तार देहरादून के पास मोहनड से शुरू होकर यह क्षेत्र तराई के आगे मैदानो पर बसे शहरों तक हो गया है। जाहिर है इससे आसपास की शहरी आबादी पर जोखिम बढ़ गया है।

अर्थक्रेक डिजाइन कोड 2025 के अंतर्गत जारी नया सिस्मेक जोनेशन मैप में इस अध्ययन का खुलासा हुआ है। इस नए मैप में पूरे हिमालय आर्क को शामिल किया गया है। मैप ने भूकंप के खतरे की वैज्ञानिकों की पूर्व अवधारणा और समझ को बदलकर रख दिया है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल फ्रंट, सिक्किम और अरुणाचल क्षेत्र को सबसे खतरनाक जॉन 6 में रखा गया है। मैप में बताया गया है कि भारत का 61 फ़ीसदी हिस्सा मध्यम से उच्च जोखिम में है। इस हिस्से में देश की तीन चौथाई आबादी निवास करती है। अध्ययन में जोखिम क्षेत्र का विस्तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रोबैबिलिस्टिक सिस्मिक हेजर्ड असेसमेंट से यह नक्शा बीआईएस ने तैयार किया है। हिमालय तथा आसपास के किन-किन क्षेत्रों में भूकंप की दृष्टि से कितना खतरा है, इसमें स्पष्ट किया गया है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय क्षेत्र को जॉन 5 और 6 में दर्शाया गया है, वहीं दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा देश के अन्य कई क्षेत्रों को यलो जोन दो-तीन और चार में रखा गया है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमें भविष्य में अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। इस तरह की आपदा भूगर्भ में पांच किलोमीटर से अधिक गहराई में होने वाली प्लेटों के खिसकने के कारण होती है। भूमि के भीतर होने वाली इन हलचलों के अनेक वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। इस तरह की आपदाओं को हम रोक नहीं सकते किन्तु सुरक्षा उपायों से इसके जोखिम को कम कर सकते हैं। शहरी नियोजन अधोसंरचना और भवन निर्माण सुरक्षा मानकों के अनुसार करना होगा। यानि ऐसे निर्माण जो भूकंप आपदा के बाद भी यथावत रहें।

मानवीय दखल बड़ी समस्या- नए अध्ययन से स्पष्ट है कि मानवीय गतिविधियां बढ़ने से हिमालय वन क्षेत्र का क्षरण हो रहा है। इससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। हमने पर्यटन की सुविधा तो बढाई परंतु पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा। इन सब कारणों से हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट छा रहा है। आबादी बढ़ने, शहरी विस्तार होने और पर्यटन बढ़ने से पहाड़ों पर मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं। वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। हिमालय की जैव विविधता- हिमालय की जैव विविधता समृद्ध और अद्वितीय है। यह भारत ही नहीं विश्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां के वन, बर्फीले पहाड़, विशाल घास के मैदान हैं। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कठबंधीय विविध क्षेत्र यहां पाए जाते हैं। यहां हजारों की संख्या में दुर्लभ किस्म के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। आयुर्वेद, यूनानी और अन्य चिकित्सा में इनका उपयोग होता है। इन पेड़ों के कारण हजारों स्थानीय लोगों की आजीविका चलती है। जीव जंतुओं में हिमालय भालू, टाइगर, तेंदुआ, हिमालय हाथी, ब्लैक बियर, विशेष है। प्रवासी पक्षियों के लिए हिमालय सुरक्षित आश्रय स्थल है। हिमालय की झीलों में जलीय जीव और मछलियों की विविध प्रजातियां हैं। समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 50 के दशक में ही हिमालय के इस संकट को पहचान लिया था, तब उन्होंने हिमालय बचाओ का नारा दिया था। उनके आह्वान पर कई संगठनों ने आवाज उठाई थी। पूर्व में डरबन में हुए सम्मेलन में भी हिमालय के बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता व्यक्त की गई थी। वैश्विक स्तर पर इस दिशा में संरक्षण की पहल होना चाहिए। स्पष्ट है कि हमें भविष्य में समावेशी विकास का मार्ग अपनाना होगा।

हिमालय के ग्लेशियर - जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालय के ग्लेशियर निरंतर पिघल रहे हैं। भविष्य में समूची मानव जाति को इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शोध कार्यों से पता चलता है कि हिमालय के ग्लेशियर हर साल एक मीटर घट रहे हैं। इनके पिघलने की यदि यही गति रही तो 2050 तक यह ग्लेशियर अपना अस्तित्व खो सकते हैं। हम जानते हैं कि इन्हीं ग्लेशियर के कारण गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा अन्य कई सहायक नदियों का जल प्रवाह होता है। इसी जल से हमारा जीवन सुरक्षित है। कई देशों के लिए यह मीठे पानी का स्रोत है। यदि नदियों पर संकट आता है तो यह समूची मानव सभ्यता पर संकट कहा जाएगा। संरक्षण का अब भी समय है। हम हिमालय के परिस्थितिकी तंत्र पर आए संकट को बचा सकते हैं।

पहल और उपाय - हिमालय क्षेत्र की विकास नीतियों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ विकास को हमें अपनाना होगा। बांध और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर अंकुश लगाना होगा। वनों की कटाई , अवैध शिकार को रोकना, पहाड़ों के खनन को रोकना और नदियों के खनन को रोकना होगा। पर्यटन को नियंत्रित करना होगा। हमें वहां की स्थानीय वनस्पतियों का संरक्षण करना होगा। पेड़ लगाते समय यह ध्यान में रखना होगा कि उनकी प्रजाति हिमालय पर्यावरण के अनुकूल हो। बांस, देवदार, ओक, चीड़ के पेड़ यहां बहुतायत में पाए जाते हैं। पूर्व में अंग्रेजों ने यहां चीड़ के पेड़ लगाए थे। यह वन काफी संख्या में है। यह पेड़ हिमालय के अनुकूल नहीं है। चीड़ के पेड़ भूजल और मिट्टी से काफी मात्रा में पोषक तत्व सोख लेते हैं। इनके स्थान पर शहतूत, पदम, चेस्टनट, अखरोट, सिरौली , चूले जैसी प्रजातियों के पेड़ हिमालय क्षेत्र में रोपित किया जाना चाहिए। रेशा और फलदार वृक्षों को हिमालय क्षेत्र में रोपण करना चाहिए। इससे हम यहां की वनस्पतियों को बचा सकते हैं।

अभ्यारण्य और मिशन की शुरुआत - जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया है। जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को उनकी पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं को शामिल किया जा रहा है। इससे वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जा सकेगा। हिमालय के महत्व को देखते हुए हिमालयि पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन शुरू किया गया है। यहां की नदियों और इस पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र पर उत्पन्न होने वाले संकट का इसमें अध्ययन करना शामिल है।

भविष्य में इसके आकलन अनुसार सुरक्षा के उपाय होने की दृष्टि से यह मिशन महत्वपूर्ण है। यह सच है कि प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, किन्तु आपदा के जोखिम को सावधानी रखकर कम कर सकते हैं। व्यवस्थित सूचना तंत्र विकसित करके, पहाड़ों और तटीय क्षेत्रों में समय पूर्व सूचना संवाद करके जनहानि को कम कर सकते हैं। हिमालय के पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इस हेतु हमें जन सहभागिता और सामुदायिक प्रयासों की पहल करना होगी। यहां का पारिस्थितिकी तंत्र बचेगा, तभी देश की नदियां बचेंगी। इन जीवनदाई नदियों से ही मानव सभ्यता का अस्तित्व रहेगा।

साइड लोअर -51

कटाक्ष

खुमानसिंह चुंडावत

लेखक व्यंग्यकार हैं।

छुक-छुक करती जीवन-रेलगाड़ी ने कब षष्ठी पूर्ति का जश्न मना लिया, यह पता ही न चला। बुद्धि तो कभी-कभी हिसाब लगाकर बता भी देती है, पर मन है कि इस यथार्थ को मानने को तैयार ही नहीं। जीवन के इस पड़ाव पर लोग उम्र को लेकर तरह-तरह के भ्रम पालते हैं और मज़े की बात यह कि हर किसी को भ्रम होता है कि इस भ्रम के बारे में बाकी सब भी उतने ही भ्रमित हैं!

इसी खयाली दुनिया में जीते हुए रेलवे का रिज़र्वेशन भरते समय मैंने भी अपनी उम्र 61 के बजाय 58 लिख दी—सोचा, चलो तीन साल की रियायत खुद को ही दे देता हूँ! पर खुद को हल्का आँकने का नतीजा यह हुआ कि रेलवे ने भी मुझे हल्के में लेकर सीट पकड़ा दी—सेकंड एसी की 'साइड लोअर - 51'।

टिकट हाथ में आते ही उम्र के पड़ावानुसार खिचड़ी विचार आने लगे। 'लोअर' देखकर भी कोई खुश हो सकता है, यह अनुभूति उस दिन हुई। पर अगले ही क्षण '51' देखकर मन उसी प्रकार चौंक गया, जैसा कि पचपन के आस-पास पहली बार किसी बच्चे ने 'भाई साहब' की जगह 'अंकल जी' कहकर संबोधित किया था। ज़िंदगी की रेलगाड़ी ऐसे रोमांचक जंक्शनों पर भी रुकेगी—कल्पना नहीं की थी।

'साइड' शब्द ध्यान में आते ही वे सब लोग और सारी घटनाएँ याद आ गईं, जिन्हें हमने साइड किया, जिनके साइड से निकल गए, या जिन्होंने हमें ही जीवन भर साइड किया। और जब 'लोअर' शब्द सामने आया तो दुनिया भर की मुफ़लिसी और ज़लालत मुँह बिचकाती हुई सामने खड़ी हो गई। तब बुद्धि ने समझाया—'धीरज धरो! थूरिया और नाथूखेड़ी जैसे फ्लैग स्टेशनों को पार करके ही तो महानगर के जंक्शन तक पहुँचे हो।'

अब बारी थी '51' की—इतना शुभ अंक, पर यहाँ शुभ कम और संशय ज़्यादा जगा रहा था। सीट की लोकेशन ठीक निकलेगी या नहीं? मन सुविधा चाहता था और शरीर आराम। पर मन था कि पीपल-पात की तरह डोलता ही जा रहा था।

दिसंबर में कन्फ़र्म टिकट मिल जाना सामान्यतः संतोष देता है, पर 'साइड लोअर 51' ने जीवन में ऊहापोह मचा दी थी। जैसे-तैसे यात्रा दिवस आ गया। स्टेशन पहुँचे। ट्रेन आई। पर उस दृश्य से बनने वाली रोमांच की लहर हमारे पास तो भटककर भी नहीं आई। हमारा ध्यान सिर्फ़ सीट की लोकेशन पर था।

कोच में घुसते ही आशंका साकार हो गई। 'साइड लोअर 51' को देखते ही वैराग्य का भाव ऐसे आया जैसे साधु को मोक्ष-दर्शन हो जाते हों। सीट पर पहले से थानेदार-सी मुद्रा में जमे हुए यात्री को टिकट दिखाकर हटाया तो गया, पर वे अपने उपभोग के सर्वाधिक क्षतिग्रस्त अवशेष वहीं छोड़ गए। सीट के नीचे का दृश्य तो ऐसा था जैसे दादाजी के कमरे में अनावश्यक सामान ठूँस दिया गया हो—आजूबाजू के सभी यात्रियों का 'कबाड़ा' वहीं जमा था।

सब हटाने-छांटने के बाद जब सीट पर बैठा, तो लगा कि चारों तरफ़ से घिर चुका हूँ—अब मुक्ति तो मंज़िल पर ही मिलेगी।

ट्रेन चलते ही लगा जैसे सफ़र आधा हो गया, पर यह तो शुरुआत भी नहीं थी। पाँच फ़ीट दो इंच की सीट पर जब पाँच फुट आठ इंच का शरीर एडजस्ट कर रहा था, तब एहसास हुआ कि रेल का सफ़र और ज़िंदगी का सफ़र सचमुच एक जैसे हैं—दोनों में आदमी लगातार खुद को समायोजित करता ही रहता है।

चादर, शरीर और सीट का जोड़-जुगाड़ चल ही रहा था कि चाय-समोसा-डिनर की पुकार लगाता वेटर जोर से धक्का मारकर निकल गया, और मैं साइड-पार्टीशन से उछलकर फिर वहीं पहुँच गया जहाँ से बिस्तर बिछाने की यात्रा शुरू की थी। जैसे-तैसे लेटा तो दरवाज़े की 'भुतहा' आवाज़ हर तीन मिनट में किसी न किसी के साथ आती और मुझे भी ठेलती हुई चली जाती—साथ ही अनचाही 'दूषित हवाओं' के झोंके छोड़ती हुई। एक भभका कटे कि दूसरा हाजिर—ज़िंदगी की तरह ही ठेलने-खेलने और फैलने-फैलाने का क्रम जारी।

अंतर बस इतना था कि ज़िंदगी में जब-जब ठंडी बयार की दुआ की, तब गर्म थपेड़े ही मिले; यहाँ ट्रेन में बिना मांगे ही एसी की ठंडी हवा सीधे चेहरे पर पड़ रही थी।

और मैं सोच रहा था— ज़िंदगी का सफ़र भी रेल-सफ़र जैसा ही है। चाहे साइड लोअर हो या साइड अपर—सीटें अलग, असुविधाएँ अलग, पर प्रक्रिया एक ही हैः चलते रहो, सहते रहो, और आख़िर में मुस्कुरा कर कहो— यही है जीवन-यात्रा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट समझे जाने की जरूरत

व्यंग्य

शांतिलाल जैन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

9 नवंबर, 2025. जैन परिवार पूर्व और वर्तमान के सभी सरकारी कर्मचारियों,अधिकारियों का आभार व्यक्त करता है. काम के प्रति आपकी उदासीनता और बेरुखी के कारण हमारा परिवार देश के विकास के लिए, सरकारी खजाने में अत्यंत मामूली ही सही, योगदान दे तो पाया है. इसका पता भी हमें आज ही अख़बारों से चला जब सरकार ने संसद में बताया कि सरकारी दफ्तरों में चले सफ़ाई अभियान में रद्दी बेचकर सरकार को चार हज़ार पिच्चासी करोड़ रुपए मिले हैं. निश्चित ही इसमें वो फाईल भी रही होगी जिसमें दादाजी ने राशनकार्ड के लिए एप्लाय किया था और ताउम्र चक्कर काटने के बाद भी बन नहीं पाया था. उस मोटी सी पेंडिंग फाईल का डब्बा-बाटली वाले ने कम से कम एक रूपया तो दिया ही होगा. राष्ट्र के विकास में हमारे साधारण से मुफ़लिस परिवार से एक रूपए का योगदान भी कम नहीं होता श्रीमान.

आप ही सोचिए, जो हमारे दादाजी ने उस समय राशन कार्ड बनवाने में टाईम वेस्ट नहीं किया होता तो आज 'वेस्ट से वेल्थ' कैसे बना पाती सरकार? फाईलों के पहाड़ों को वेस्ट नहीं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखे जाने की जरूरत है. देशभर में लाखों बाबूओं ने जो अपनी काहिली, कामचोरी और भ्रष्टाचार से आम आदमी को यह इन्वेस्टमेंट करने के लिए विवश नहीं किया होता क्या आज सरकार चार हज़ार करोड़ कमा पाती!! जो कागज़ कभी आम नागरिकों को उनके अधिकार नहीं दिला पाए अब सरकार का रेवेन्यू मॉडल बन चुके हैं.

फिर बात सिर्फ आर्थिक योगदान की नहीं है, मंत्रीजी ने यह भी बताया कि 'ज़्यादातर पेंडिंग फाइलें और दूसरे पेपरवर्क के रूप में अटाला हटाने से 923 लाख वर्गफुट ऑफिस स्पेस खाली हुआ, इतनी जगह में एक बड़ा मॉल या वैसी ही बड़ी बिल्डिंग बन सकती है. जैन परिवार के राशन कार्ड की फाईल ने एक वर्गफुट जगह भी खाली करने में मदद की हो तो इसे मामूली योगदान न समझा जाए श्रीमान. हम दादाजी के लिए कोई पद्म पुरस्कार नहीं मांग रहे, उनके योगदान की पावती भर मिल जाए, बस. लेमिनेट करा कर उनकी तस्वीर के बाजू में लगाकर हम उन्हें सच्ची श्रृद्धांजलि देना चाहते हैं. इससे हमारा अपराध बोध कम होगा. अब तक हम उन्हें झक्की इंसान समझते रहे. उस ज़माने की प्रचलित दरों के अनुसार उन्होंने पाँच रूपए की रिश्वत दे दी होती तो महज़ एक पेज की दरख्वास्त में उसी समय काम हो गया होता. वे झक्की नहीं दूरदर्शी थे. पहले एप्लीकेशन, फिर एफिडेविट, फिर मूलनिवासी का प्रमाणपत्र, फिर रिमाइंडर, रि-एप्लाय, रि-रिमाइंडर के कागज़ सबमिट कर-कर के देश के खजाने में तभी अपना योगदान करके चले गए. वे बो गए थे, सरकार काट रही है.

बहरहाल, आज से जैन परिवार सरकार का मुरीद हो गया है. उसने अब जाकर यह रियलाइज़ किया है कि बेचने के मामले में सरकार की नज़र में सब समान है. वह सरकारी दफ्तरों से निकले जूने-पुराने अटाले को भी उसी शिद्दत से बेच लेती है जिस शिद्दत से एयरलाईंस, पोर्ट, एयरपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्यमों को बेच लेती है. जब बेचने ही निकले हैं श्रीमान् तो क्या लकड़ी के जंगल और क्या लकड़ी की टूटी कुर्सी!! सरकार वेस्ट बेचकर वेल्थ बनाने के मिशन पर काम कर रही है. इस बेचने को सरकार बेचना कहती भी नहीं, असेट मोनेटाईजेशन कहती है.

नेशन के लिए असेट मोनेटाईजेशन में अपने अल्प किन्तु महत्वपूर्ण योगदान से जैन परिवार गौरवांवित अनुभव करता है और उन सभी बाबूओं का आभार व्यक्त करता है जिनकी काहिली, लापरवाही, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के कारण जैन परिवार को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है. आभार.

मोहन सरकार के दो वर्ष

सुरेश पचौरी

लेखक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं।

डॉ. मोहन यादव सरकार के बेमिसाल दो साल

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में गतिशील सरकार 13 दिसम्बर 2025 को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरा कर रही है। इस अवधि पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि विगत 2 वर्षों में सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी नीतियों, सतत् संचालित विकास कार्यों तथा योजनाओं के लोकव्यापीकरण से प्रदेशवासियों का दिल जीतने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के ठीक बाद कहा था कि मेरी प्राथमिकताओं में समाज का वह सर्वहारा वर्ग प्रमुखता से शामिल है, जिसे सरकार से मदद की दरकार है और जिसने बड़ी आशा के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकहितैषी सरकार बनाने में अपना अहम् योगदान दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी सरकार जनता की भलाई की दिशा में इतने ज्यादा उल्लेखनीय कार्य करेगी, जिससे मध्यप्रदेश विकास का एक अनुकरणीय मॉडल बनेगा। फिलहाल डॉ. यादव अपने कथन को फलीभूत करने में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ जी-जान से कटिबद्ध हैं। वे अपने उन सत्संकल्पों की प्रतिपूर्ति के लिए न सिर्फ शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, बल्कि एक सदाशयी जननेता के रूप में मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर ले जाने की पुरजोर काशिश कर रहे हैं।

आज मध्यप्रदेश में चतुर्दिक विकास का पहिया घूमता हुआ आपको नजर आएगा। चाहे बिजली का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला हो, चाहे सिंचाई योजनाओं का विस्तार हो, चाहे उद्योग धंधों की स्थापना हो या फिर हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने की नल-जल योजना हो अथवा सुदूर आदिवासी इलाकों में शिक्षा व इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना हो, सरकार की ओर से आम आदमी को सुविधा तथा संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। गांव, कस्बा, नगर, शहर सर्वत्र नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही समस्या का निवारण हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रदेश के लाखों अन्नदाता किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, अपराधों में कमी आई है, गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जा रही अनेक योजनाएं तो देश के अन्य राज्यों के लिए नजीर बन चुकी हैं।

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वादे चुनाव के दौरान किए गए थे वे पूरे किए जा रहे हैं। यद्यपि किसी भी सरकार के लिए 2 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं माना जा सकता लेकिन डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार घोषणा पत्र में उल्लेखित एक-एक बिंदु को योजनाबद्ध तरीके से अमलीजामा पहना रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न इलाकों में बंटे मध्यप्रदेश के प्रत्येक भू-भाग में समरस भाव से विकास कार्य किए जा रहे हैं। न किसी तरह का भेदभाव है, न किसी क्षेत्र की उपेक्षा। शासन का लक्ष्य समूचे मध्यप्रदेश का सर्वांगीण विकास कर उसे एक विकसित व आदर्श राज्य बनाने का है। मुख्यमंत्री जी ने तो सभी विधायकों से यहां तक कह दिया है कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए पूरे पाँच साल का प्लान बनाकर हमें दीजिए, हम उसे पूरा करने के लिए भरपूर राशि उपलब्ध कराएंगे। धन के अभाव में विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सदाशयता का परिचायक तो है ही, साथ ही प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की उनकी सरकार की संकल्पबद्धता भी है।

शाश्वत सत्य है कि यदि सही नीति और अच्छी नीयत के साथ कुशल व संवेदनशील नेतृत्व हो तो उसके परिणाम बहुत सुखद होते हैं। मध्यप्रदेश को इस मामले में सौभाग्यशाली राज्य माना जा सकता है कि इसे जहां एक ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मार्गदर्शन व वरदहस्त प्राप्त है तो दूसरी ओर है कर्मठ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कुशल नेतृत्व। प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री की नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका इजहार भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कई बार मध्यप्रदेश की सम-सामयिक उपलब्धियों का जिक्र कर चुके हैं। यह तो एक बानगी है। मध्यप्रदेश में महिलाओं, किसानों, युवाओं, वंचितों, निराश्रितों एवं जरूरतमंदों की भलाई के साथ-साथ स्व-सहायता समूहों के उत्थान के लिए इतने काम हुए हैं, जो बेमिसाल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कथन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत निर्माण के लिए ज्ञान (GYAN) गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सम्मान की जो बातें की हैं, वे हमारी सरकार के लिए ब्रह्मय वाक्य है। इन्हीं चार आधार स्तंभों पर केन्द्रित समग्र विकास का रोडमैप मध्यप्रदेश में भी तैयार किया गया है और उसी दिशा में प्रदेश सरकार सेवारत है। प्रदेश सरकार गरीब कल्याण, युवा शक्ति, किसान कल्याण और नारी शक्ति मिशन लागू कर अंतिम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के कल्याण और उसके बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु अवसर उपलब्ध करा रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की जो गंगा प्रवाहित हो रही है उससे मध्यप्रदेश भी अछूता नहीं है। पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन में संचालित केन्द्रीय योजनाओं का मध्यप्रदेश को भरपूर लाभ मिल रहा है। केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन से उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने में मध्यप्रदेश देश में लगातार अग्रणी बना हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण) आयुष्मान भारत योजना आदि।

विगत 2 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात की जाए तो मध्यप्रदेश में भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11 लाख 46 हजार आवास से मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 8 लाख 64 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। गरीब बंदी सहायता योजना का क्रियान्वयन करने वाला प्रथम राज्य बना है। प्रदेश में 80 लाख 52 हजार घरों तक नल कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में लगभग 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को कुल 8 हजार 690 करोड़ से अधिक का लाभ प्रदान किया गया। प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की 1671.00 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। आयुष्मान निरामयम भारत योजनांतर्गत 3 लाख एक हजार 496 परिवारों के सदस्यों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। राज्य में मातृ शक्ति को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं का 512 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई।

मध्यप्रदेश में निवेश

भोपाल में पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। इसके उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और समापन अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी विकसित राज्य बनाने के मुख्यमंत्री के अथक परिश्रम और दृढ इच्छाशक्ति की प्रशंसा की। प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अंतर्गत अब तक 8.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता योजनांतर्गत 1 लाख 52 हजार 353 हितग्राहियों को सहायता राशि रुपए 83844.39 लाख दी गई।

सिंहस्थ

मध्यप्रदेश सरकार के सामने आने वाले दिनों में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ पर्व को सुसम्पन्न कराने की एक बड़ी चुनौती है। इस धार्मिक समागम में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इसे निर्विघ्न व गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही शासन-प्रशासन के अधिकारियों को सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां करने के निर्देश दे दिए थे, ताकि सारे काम समय पर पूरे हो जाएं। इसके लिए यथासमय बजट का आवंटन किया गया। वर्ष 2025-26 में सिंहस्थ 2028 के लिए 67 आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। सिंहस्थ के अवसर पर दुनिया भर से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं तथा तीर्थयात्रियों को किसी तरह की तकलीफ न होने पाए, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक पहचान रखने वाले प्रमुख स्थानों के साथ ही पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के चित्रकूट, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर आदि स्थानों को उनके प्राचीन गौरव, वैभव और गरिमा के अनुसार सजाया-संवारा जा रहा है। मध्यप्रदेश में द्रुत गति से विकास के काम जारी हैं। श्रीराम वन गमन पथ श्रीराम के कर्तव्य पालन और राष्ट्र निर्माण का समर्पण संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का आधार देगा। साथ ही राज्य शासन द्वारा उन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ श्रीकृष्ण के स्मृति चिन्ह विराजमान हैं।

मध्यप्रदेश में नक्सल समस्या

मध्यप्रदेश में नक्सल मोर्चे पर सबसे बड़ी कामयाबी दर्ज की गई है। मध्यप्रदेश में 2.36 करोड़ रुपए के इनामी 10 हार्डकोर नक्सलियों ने एके-47 समेत आई.एन.एस.ए.एस. राइफल, एस.एल.आर. और सिंगल शॉट गन जैसे घातक हथियारों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है।

निःसंदेह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के हितों के मद्देनजर तमाम लोककल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निष्ठापूर्वक राजधर्म निभा रही है तथा एक लोकप्रिय सरकार बनने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रही है। भौगोलिक दृष्टि से देश के इस बड़े राज्य के सामने जहां तमाम चुनौतियां हैं, वहीं जनता की अनगिनत अपेक्षाएं भी हैं। सरकार चुनौतियों से भी निपट रही है और जनापेक्षाओं को भी पूरा कर रही है। विकास सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और आशा की जानी चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार विकास के रथ को रुकने नहीं देगी। मध्यप्रदेश सरकार के उपलब्धियों भरे 2 वर्ष पूरे होने के अवसर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के ऊर्जावान सहयोगियों, राज्य की प्रशासनिक टीम तथा प्रदेश की जागरूक जनता को हार्दिक बधाई।

मोहन सरकार के दो वर्ष

डॉ. हरीशकुमार सिंह

विकसित मध्यप्रदेश के लिए मोदी की राह पर मोहन

मध्यप्रदेश के उन्नीसवें मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव अपने कार्यकाल का दूसरा सफल वर्ष 13 दिसम्बर को पूर्ण कर रहे हैं। दो वर्ष के मुख्यमंत्री काल में डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने प्रतिदिन अपने आपको प्रदेश के विकास के कार्यों के लिए व्यस्त रखा। मुख्यमंत्री ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और लगातार प्रदेश के लिए भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर जनसेवा में लगे रहे। जहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाते थे उन्होंने अपनी उपस्थिति वीसी के माध्यम से दर्ज कराई। मुख्यमंत्री की यह कार्यशैली देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तर्ज पर रही है कि प्रतिदिन बिना थके राष्ट्रहित में अठारह घंटे कार्य करना ही है। मोदी जी के विजन को सीएम मोहन यादव ने अपना मिशन बनाया है।

प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा यूके, जर्मनी, जापान के साथ पुणे, गोवाहाटी, रीवा, कोलकाता में निवेश के लिए लगातार बैठकें और समीक्षा की। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ है। प्रदेश की गौशालाओं की स्थिति में सुधार के लिए दौरे और अनुदान, प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए नवीन कार्य, विक्रमोत्सव में राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन जैसे नवाचार, लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत आयुष-आयुर्वेद को बढ़ावा, जल गंगा संवर्धन अभियान में जल के नवीन श्रोतों की खोज और पुनरुद्धार, सोलर परियोजनाओं में बढ़ोतरी, समूहिक विवाह को प्रोत्साहन, रीजनल टूरिज्म, स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिकता, नवीन उद्योगों का सृजन, युवाओं को नवीन सरकारी नौकरियों की दिशा में कार्यान्वयन और आने वाले समय में ढाई लाख भर्तियों की योजना, स्वरोजगार के लिए बेरोजगारों को ऋण और स्टाइपेंड, पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन, सिंहस्थ के लिए पांच हजार होमगार्ड की नई भर्ती, मोदी जी की तर्ज पर चीता प्रोजेक्ट और नई नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करना, नए मेडिकल कॉलेज के लिए सघन प्रयास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना। यही नहीं सरकारी राज्य परिवहन को फिर से जीवित किया जा रहा है।

प्रदेश में जिन मुद्दों पर कार्य और तेजी से अपेक्षित हैं उनमें वर्ष 2026 चूंकि 'समृद्ध किसान 'समृद्ध प्रदेश' की थीम पर कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा इसलिए भविष्य में प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में सुगमता से खाद वितरण सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य विभाग के सभी पदों पर शीघ्र भर्ती, अपराध और अपराधियों पर कड़ा नियंत्रण, शहरों के स्थानीय निकायों को उचित धन और अनुदान देना, विकास के नए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रबंधन, पेट्रोल डीजल से वेट कम करना, विभागीय भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, थानों में आमजन के साथ सद्व्यवहार आदि हैं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र की मंशा के अनुरूप प्रदेश में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सम्पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को समय के पहले ही प्राप्त कर लिया है। बालाघाट में दस नक्सलियों का एके 47 जैसे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण सबसे बड़ी उपलब्धि रही और इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास - पुनर्जीवन किया जाएगा। नक्सलियों के आत्मसमर्पण का यह अभूतपूर्व कार्य बड़े पैमाने पर प्रदेश में पहली बार हुआ है और इसके पहले वर्ष 1983 में मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह के कार्यकाल में चम्बल-भिंड में दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने जरुर अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। नक्सलवाद मुक्त मध्यप्रदेश की दिशा में यह एक सशक्त कदम है।

1980 के सिंहस्थ से ही यह संयोग बना है कि जब-जब उज्जैन में प्रति बारह वर्ष में सिंहस्थ का आयोजन हुआ है प्रदेश में भाजपा सरकार की देखरेख में ही सिंहस्थ भव्यता से संपन्न होता आया है। ऐसे में सिंहस्थ के आयोजन के समय उज्जैन से राज्य सरकार में मंत्री, कई स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे पर पहली बार उज्जैन का जनप्रतिनिधि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उज्जैन में सिंहस्थ के आयोजन का साक्षी बनेगा। ऐसे में उज्जैन को सिंहस्थ के नाम पर श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों और शहरवासियों के लिए उज्जैन को सैकड़ो सौगातें और हजारों करोड़ के विकास कार्य मिले और मिल रहे हैं जिससे महाकाल की नगरी आगामी 2028 के सिंहस्थ के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत भव्य रूप से करती नजर आएगी। कान्हा क्लोस डक्ट,सेवरखेडी - सिलारखेडी- हरियाखेडी एकीकृत परियोजनाओं से शिप्रा को स्वच्छ, अविरल और प्रवाहमान बनाया जा रहा है। सिंहस्थ में स्नान के लिए तीस किमी तक के नये घाट बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आगामी सिंहस्थ के लिए अपनी जो महत्वाकांक्षी लैंडपुलिंग योजना लेकर आये थे वह अब किसानों से बनी सहमति के बाद वापस ले ली गई है और यह निर्णय बताता है कि मुख्यमंत्री ने किसानों की मांग मानने में तनिक देर नहीं की। जबकि पिछले सिंहस्थ में आई आंधी-बारिश से कई तम्बू उखड़ गये थे और कीचड़ से भारी परेशानी हुई थी और संतों ने पक्की सड़कें आदि न होने पर नाराजगी व्यक्त की थी। पक्के निर्माण होने से संतों को ही राहत मिलती मगर बिना देर किये प्रदेश शासन ने इस योजना को वापस लिया जो किसान हित में एक संवेदनशील मुखिया ही कर सकता था। धर्म, अध्यात्म के साथ विज्ञान का संगम और लोकसंस्कृति से समृद्धि के आयोजन के माध्यम से प्रदेश को 2047 तक विकसित मध्यप्रदेश बनाना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का लक्ष्य रहा है। इस दिशा में उनकी सरकार कार्य कर परिणाम प्रस्तुत कर रही है।

धरोहर

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच उ.प्र. के संस्थापक हैं।

विश्व विरासत सूची में शामिल दीपावली के निहितार्थ

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 16 नवम्बर, 1945 को स्थापित एक विशेष शाखा 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (यूनेस्को) की अंतर सरकारी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर समिति की लाल किला, नई दिल्ली में आयोजित 20वीं बैठक में घोषित नये विश्व विरासत सूची में दीपावली पर्व का शामिल किया जाना हर भारतीय के लिए गर्व, गरिमा एवं गौरव का आनंददायी अवसर है, साथ ही वैश्विक संदर्भ में सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा, प्रखरता एवं प्रदीप्ति की मानवीय भावदृष्टि वसुधैव कुटुम्बकम् की मधुरता एवं आत्मीयता के विशेष संदेश का सम्प्रेषण भी है। विश्व विरासत सूचिका के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर वर्ग में शामिल भारत की 16वीं धरोहर दीपावली प्रकारांतर से लोक-मंगल के आराधक श्रीराम की जागतिक भूमिका की स्वीकृति है, क्योंकि लंका विजय पश्चात् अयोध्या आगमन पर नगरवासियों ने गोघृत के दीप जला कर न केवल उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया था बल्कि प्रकाश के माध्यम से एक राजपुरुष की व्यष्टि से समष्टि की, वामन से विराट की सामाजिक एवं सांस्कृतिक यात्रा तथा लोक सम्पर्क एवं लोक संग्रह से निरंकुश सर्वोच्च अमानवीय सत्ता पर वनवासी-गिरिवासी समाज की विजय का यशोगान ही है। राम व्यक्ति नहीं एक संस्कृति हैं, सहकार भाव हैं। राम मानवीय मूल्यों का सर्वोच्च शिखर हैं जहां संवेदना, सह-अस्तित्व, सख्य, स्वीकृति, समन्वय, सम्बल एवं समानुभूति का इंद्रधनु मुस्कुरा रहा है, जहां करुणा का गैरिक ध्वज अपनी आभा से दैदीप्यमान हो फहर रहा है। वस्तुतः श्रीराम मानवीय आचरण की गरिमा का आख्यान हैं। राम भारत की आत्मा हैं, प्राण हैं एवं सनातन संस्कृति के आधार तत्व भी है। दीपावली राम के आदर्शमय जीवन एवं लोक व्यवहार की संवाहिका है। दीपावली का प्रकाश समता, समरसता के साथ ज्ञान की साधना का परिचायक है। दीपावली का विश्व धरोहर में चुना जाना न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा, अपितु दीपोत्सव के सांस्कृतिक वैभव से परिचित भी कराएगा।

अमूर्त धरोहर मानव जीवन से जुड़े वे पारम्परिक शिल्प कौशल, व्यवहार, नाट्य कला प्रदर्शन, सामाजिक रीति एवं प्रथाएं, अनुष्ठान, प्रकृति से जुड़ा लोक ज्ञान जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता हो तथा मौखिक शास्त्रीय वाचन आदि हैं जो मानवीय मूल्यों, संस्कृति-सभ्यता का रक्षण कर वैश्विक पहचान स्थापित करें। अमूर्त धरोहरें अनुभूतिपरक होती हैं, उनका स्पर्श एवं दर्शन सम्भव नही। दीपावली के पूर्व 15 अमूर्त धरोहरों को स्थान मिला चुका था जिनमें गरबा, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, योग, वैदिक मंत्र पाठ, कुटियाट्टम नाट्य कला, छाऊ लोकनृत्य, कालबेलिया नृत्य, रामलीला, लद्दाख का बौद्ध जप अनुष्ठान, मणिपुर भक्ति संकीर्तन, राममन कला, पंजाब की पीतल-तांबे से बर्तन बनाने की पारम्परिक लोककला आदि हैं। स्थूल सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों में अंजता-एलोरा की गुफाएं, आगरा किला एवं ताजमहल, हम्पी स्मारक, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, भीमबेटका शैल चित्र, एलिफैंटा गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, गोवा के गिरजाघर व मठ, खजुराहो के मंदिर, सांची

स्मारक, चोल मंदिर, हुमायूं का मकबरा, मानस वन्यजीव अभयारण्य, जंतर-मंतर जयपुर, पश्चिमी घाट, राजस्थान के किले, रानी की बावड़ी, अहमदाबाद एवं जयपुर शहर, सुंदर वन, महाबोधि मंदिर गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, शांतिनिकेतन तथा नालंदा महाविहार आदि स्थल शामिल हैं।

विश्व धरोहर सूची में दुनिया में भारत छठे क्रम पर है जिसकी कुल 45 धरोहरें सूचीबद्ध हुई हैं।

विश्व धरोहर स्थल वे सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रचनाएं हैं जिनको ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक महत्व एवं अवदान कारण यूनेस्को की एक अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। सम्पूर्ण मानवता के लिए असाधारण योगदान के कारण उनको अमूल्य माना गया है। इसके अंतर्गत प्राचीन खंडहर, ऐतिहासिक भवन एवं महल, किले, शहर, रेगिस्तान, गुफाएं, द्वीप, झीलें, स्मारक, पहाड़, निर्जन क्षेत्र एवं अमूर्त विचार-दर्शन, पर्व-त्योहार आदि परिगणित हैं। नई दिल्ली बैठक, दिसम्बर-2025 तक 170 देशों के 1250 से अधिक धरोहरों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। 16 नवम्बर, 1972 को विश्व धरोहर सम्मेलन में विश्व धरोहरों को सूचीबद्ध कर संरक्षित करने काम हाथ लिया गया था। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं मिश्रित धरोहरों को चिह्नित कर मानवीय अतिक्रमण, पालतू एवं वन्यजीवों द्वारा नुकसान से बचाव एवं प्राकृतिक आपदाओं से इन धरोहरों का संरक्षण एवं रखरखाव का काम किया जाता है। साथ ही डिजिटल एवं सामान्य दस्तावेजीकरण कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार कर सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पारस्परिक समझ एवं योगदान से सांस्कृतिक समृद्धि का कोष पल्लवित होता रहे। भारत ने 14 नवम्बर, 1977 को विश्व धरोहर सम्मेलन के प्रस्तावों को स्वीकार किया था। किसी धरोहर को सूची में आने के लिए निर्धारित दस मानदंडों में से न्यूनतम एक मानदंड को पूरा करना होता है। सर्वप्रथम सदस्य देश अपनी धरोहर को अस्थायी सूची में पंजीकरण हेतु आवेदन करते हैं, तत्पश्चात् वार्षिक बैठक में विचार-विमर्श से निर्णय लेकर घोषणा की जाती है।

यूनेस्को द्वारा धरोहरों का संरक्षण मानवता के लिए अप्रतिम योगदान है, जिससे काल के प्रवाह से इन महत्वपूर्ण स्थलों को बचाकर आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता रहेगा और अपनी विरासत पर गर्व करने के पल सहज प्राप्त होते रहेंगे।

मोहन सरकार के दो वर्ष

सत्ता की चकाचौंध में 'तंत्र' कहां खो गया है?

राजीव खण्डेलवाल
(लेखक कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल नगर सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

विगत दिवस देश के ''चकाचौंध'' से भरे दो ऐसे परिदृश्य सामने आए, जो ''तंत्र'' की वास्तविक स्थिति का आईना दिखाते हैं। ये दो उदाहरण बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देश की चमक-दमक और जमीनी वास्तविकताओं के बीच खाई कितनी बड़ी है।

निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रिकॉर्ड विस्तार हुआ है। 2014 में देश में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, जो ''उड़े देश का आम नागरिक'' (DAN) योजना के तहत बढ़कर आज 157 हो गए हैं। इसी अवधि में व्यावसायिक विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 860 हो गई-लगभग 115 प्रतिशत वृद्धि।

फलस्वरूप आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है।

प्रधानमंत्री का ''हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में'' का वादा निश्चय ही इस विस्तार के पीछे प्रमुख आधार रहा है। एयरपोर्ट्स का आधुनिकरण इतना प्रभावी है कि भीतर प्रवेश करते ही ''विदेश'' होने की ''सुखद'' अनुभूति होती है।

उक्त विकास ने एक नई गंभीर समस्या भी पैदा कर दी, जिसने वर्तमान संकट को गहराया है। विमानन बाजार पर आन इंडिगो (64 प्रतिशत) (2014 के 31.8 प्रतिशत से बढ़कर) और एयर इंडिया (27.3 प्रतिशत) (8.4 प्रतिशत से बढ़कर) तथापि कुल 91.3त्न नियंत्रण का व एकाधिकार, पिछले चार-पांच दिन से हो रही हवाई यात्रियों की परेशानी का एक सबब है। देश का सबसे बड़ा (आठ) निजी एयरपोर्ट प्रबंधन अदानी समूह का दबदबा भी इसी दिशा की ओर संकेत करता है।

देश की सबसे बड़ी ''फ्लाइट ट्रेनिंग एवं सिमुलेशन संस्था'' (FSTC) के 72.8 प्रतिशत शेयर उड़ाने रद्द होने के संकट पैदा होने के कुछ दिन पूर्व 27 नवम्बर को अदानी समूह द्वारा अधिग्रहित किए गए। यह भी एविएशन क्षेत्र में संभावित नई ''आशंका'' की ओर इंगित करता है। यह ''संयोग है अथवा प्रयोग''?

इसी बीच देश में 4 दिसंबर से 3000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और हजारों उड़ानें देरी से चलीं। यात्री हवाई अड्डों पर बेहाल और असहाय से दिखे। हमेशा की तरह मेनस्ट्रीम मीडिया प्रायः मौन रहा। यद्यपि देश की हवाई यात्राओं की दुर्दशा ''अर्णब'' (रिपब्लिक टीवी) की आत्मा को शायद कुछ समय के लिए जरूर जागृत कर दिया। वास्तविक तस्वीर सोशल मीडिया पर ही सामने आयी।

मूल समस्या पायलटों की भारी कमी थी। आवश्यक संख्या - 2422 उपलब्ध -1357

कम से कम 650-700 अतिरिक्त पायलट की जरूरत थी, जिसे कंपनी ने अनदेखा किया।

इंडिगो ने पायलट नहीं बढ़ाए, जबकि टाटा एयरलाइंस ने समय रहते 350 से अधिक पायलट नियुक्त किए, इसलिए उनका निरस्तीकरण मात्र 1-2त्न रहा।

पायलट यूनियंस FIPऔर ALPA ने इंडिगो की ''लीन मैनपावर स्ट्रैटेजी'' (हायरिंग फ्रीज, पाय फ्रीज, नॉन-पोचिंग एग्रीमेंट्स) की कड़ी आलोचना की है, तथापि कोई आधिकारिक हड़ताल घोषित नहीं हुई। क्या इसका एक मतलब यह भी निकलता है की इंडिगो कंपनी ने FDTL नियम को लागू न करने के लिए ही से यह स्थिति निर्मित की? जिसमें वह सफल भी रही, क्योंकि डीजीसीए ने कंपनी को कोई सजा दिए बिना उक्त नियम लागू करने के लिए फरवरी 2026 तक का समय और दे देकर पायलट व यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। जबकि दूसरी कंपनी एयर इंडिया में उक्त नियम का लगभग परिपालन किया।

हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 22 माह पूर्व (जनवरी 2024) में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम जारी किए थे। उनका उद्देश्य था, पायलट की ''थकान'' (फिटीग) कम करना। क्योंकि हवाई दुर्घटनाओं के पीछे 10-15त्न कारण ''थकान'' ही पाया गया था। परंतु इंडिगो के समय बढ़ाने के बार-बार अनुरोध और दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से इन्हें चरणबद्ध तरीके से 1 जुलाई एवं 1 नवंबर 2025 से लागू किए गए। नियम लागू होने पर उसके परिपालन में कंपनी ने पायलट (300 कप्तान व 600 फर्स्ट ऑफिसर) बढ़ाने की जगह उड़ानें ही रद्द कर दीं। जबकि टाटा एयरलाइंस 350 पायलट हायर कर उनकी फ्लाइट निरस्तीकरण मात्र 1-2 प्रतिशत की रही। सबसे चौंकाने वाली बात ऐसी मनमानी के लिए कंपनी को दंडित करने के बजाय डीजीसीए ने अपने बनाए नियम ही फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिए!

यही नहीं, मांग व पूर्ति के दबाव में अन्य हवाई कंपनियों के टिकट 6 गुना तक महंगे हो गए। संकट पैदा होने पर संकट पैदा करने वाली कर उस संकट का फायदा लेने वाली कंपनी दोनो को एक साथ फायदा देना यही तो डीजीसीए का ''कमाल'' है। राजनीतिक नेतृत्व भी ''सपनों की उड़ान में सोया हुआ है।'' डीजीसीए का अधिकतम 18,000 रु. किराया निर्धारित करने का आदेश भी ''हवा-हवाई'' हो गया। एक उदाहरण-जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के सी त्यागी, पूर्व सांसद को अपनी बेटी को मुंबई परीक्षा में भेजने के लिए रू. 9000 की इंडिगो की फ्लाइट निरस्त होने पर मजबूरी में एयर इंडिया की टिकट रू. 41,000 में लेनी पड़ी। इसकी रिफंड की मांग भी त्यागी ने की है, न होने पर धरने पर बैठने तक की धमकी तक दे दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का लोकसभा में यह बयान बेहद हास्यास्पद है कि पूरी जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? याद कीजिए! अहमदाबाद हवाई दुर्घटना की क्या कोई जांच रिपोर्ट आपके सामने आई? ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है?

दूसरा उदाहरण और भी प्रतीकात्मक है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 7, लोक कल्याण मार्ग पर स्थित सरकारी आवास ''पंचवटी'' में आयोजित रात्रि-भोज की फोटो स्वयं प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X(एक्स) पर साझा की। यदि आप ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री'' के आवास के प्रवेश द्वार के फाउंटेन कुछ जर्जर होकर पानी पूरी तरह से साफ नहीं है। ''स्वच्छ भारत'' अभियान के ''प्रणेता'' के सरकारी निवास की यह स्थिति किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की ढिलाई का उदाहरण है। इस अभियान पर अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 12192 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके मूलभूत रखरखाव भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

इन दो उदाहरणों से स्पष्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ही पर्याप्त नहीं, उसे नियंत्रित व संचालित करने वाला 'तंत्र' भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। दुर्भाग्य वश यही तंत्र आज पूरी तरह विफल दिखाई दे रहा है।

विकास केवल इमारतें, रनवे, या चमकती सड़कों से नहीं होता- बल्कि उनको संचालित नियंत्रण रखने वाली संस्थाओं की मजबूती से होता है। दुर्भाग्य से आज यही तंत्र सबसे अधिक कमजोर, अकर्मण्य और असफल दिखाई देता है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है न तो यह नियंत्रण तंत्र दोषी कंपनी को सजा देने का आशय रखता है और न ही सरकार इस अपने दायित्व को निभाने में इस असफल तंत्र को सुधारने की आशय रखती है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सेन समाज विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सेन का किया अभिनंदन

देहदान संकल्प को बताया समाजहित एवं मानवता के लिए अनुकरणीय कदम

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल में सेन समाज विकास संगठन, मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक सेन का देहदान संकल्प के लिए अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्री सेन द्वारा समाजहित में

उठाए गए देहदान के संकल्प को गहन संवेदनशीलता और मानव सेवा के सर्वोच्च मूल्यों से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि देहदान का निर्णय प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने कहा कि श्री अशोक सेन का यह कदम समाज में देहदान एवं अंगदान को लेकर सकारात्मक सोच और जागरूकता बढ़ाएगा, तथा अनेक लोगों को जीवनरक्षक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह संकल्प मनुष्य जीवन की महत्ता और समाजहित के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार अंगदान और देहदान को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने समाज सेवा के निरंतर प्रयासों की सराहना की और उनके उत्तम स्वास्थ्य व की शुभकामनाएँ दीं।

7 करोड़ की आबादी पर 12.84 करोड़ जाँच, साइंस हाउस का फर्जीवाड़ा खुद आँकड़ों से बेनकाब : जयवर्धन सिंह

भोपाल। आज मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, विधायक ऋषि अग्रवाल, विधायक देवेंद्र पटेल, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव उपस्थित रहे। विधायक जयवर्धन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में 943 करोड़ रुपये के कथित महाघोटाले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि विभाग ने विधानसभा में 68 हजार पन्नों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, जिनके प्रारंभिक अध्ययन में यह सामने आया कि 7 करोड़ की आबादी पर 12.84 करोड़ जाँचें दिखाकर फर्जी बिल बनाए गए। एक ही व्यक्ति की दो कंपनियों को अलग-अलग नाम से टेंडर दिया गया। एक ही टेस्ट के अलग-अलग रेट लगाकर भारी लूट हुई। 0 प्रतिशत जीएसटी वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला गया। श्री जयवर्धन सिंह ने कहा यह वही कंपनी है जिस पर ईडी और इंकम टेक्स की कार्रवाई हो चुकी है और मालिक जेल जा चुका है, फिर भी भाजपा सरकार ने जुलाई 2025 में इसे एक वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया। स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा को निजी कंपनियों के हवाले कर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं मांग करता हूँ कि पूरे प्रकरण की CBI जाँच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। यह भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के लोगों की सेहत के साथ किया गया अपराध है।

दुबई से चलता था अवैध सट्टाबाजी नेटवर्क, 6 अपराधी गिरफ्तार

9.84 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, 20 एटीएम, 8 पासबुक, 4 मोबाइल जब्त

बैतूल। बैतूल पुलिस ने एक संगठित साइबर धोखाधड़ी और अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क का खुलासा किया है। करीब 9.84 करोड़ के इस विशाल नेटवर्क को तोडऩे के लिए पिछले एक महीने से साइबर सेल और एसआईटी की संयुक्त टीम गुपचुप तरीके से काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन और एएसपी कमला जोशी के निर्देशन में चल रहे इस ऑपरेशन का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता गया और आखिरकार वह जाल सामने आया, जो बैतूल से लेकर इंदौर और फिर दुबई तक फैला हुआ था। शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में संगठित साइबर धोखाधड़ी और अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20 नवंबर को पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी राजा उर्फ आयुष चौहान, अंकित राजपूत और नरेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया था, वहीं 7 दिसंबर को अमित अग्रवाल को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क में होने वाले कैश ट्रांज़ैक्शन का प्रमुख माध्यम अंकित राजपूत था। अमित अग्रवाल ने अंकित की मुलाकात ब्रजेश महाजन से करवाई, जिसके बाद साइबर ठगी और बेटिंग नेटवर्क आपस में जुड़े। अमित ने अंकित को अपने घर में किराए पर रखा और अवैध लेन-देन का पूरा तंत्र चलवाता था। अवैध कमाई का उपयोग कर अमित अग्रवाल ने बीएमडब्ल्यू कार और एक आलीशान बंगला भी खरीदा था। पुलिस ने 11 दिसंबर को दो प्रमुख आरोपी राजेन्द्र राजपूत और ब्रजेश महाजन को इंदौर से गिरफ्तार किया। राजेन्द्र राजपूत एटीएम विड्रॉल म्यूल खातों से नकदी निकालता था और अंकित राजपूत के निर्देश पर विभिन्न स्थानों से रकम जुटाता था। कैश नेटवर्क का मुख्य संचालक सभी कार्य अंकित के माध्यम से नियंत्रित करता था।

डिजिटल सामग्री का फॉरेंसिक विश्लेषण कर रही पुलिस

पुलिस डिजिटल सामग्री का फॉरेंसिक विश्लेषण और अवैध ऑनलाइन बेटिंग एवं साइबर ठगी नेटवर्क की मनी ट्रेल सहित अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने कहा कि ऐसी वेबसाइटें न केवल आर्थिक अपराध को बढ़ाती हैं बल्कि युवाओं को गलत दिशा में ले जाती हैं। पुलिस ने नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि अवैध बेटिंग से दूरी रखें और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। एसपी वीरेंद्र जैन ने मामले में उत्कृष्ट समन्वय, त्वरित कार्रवाई और निरंतर निगरानी के लिए संपूर्ण टीम की प्रशंसा की।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

इस मामले का खुलासा करने में डीएसपी दुर्गेश आर्मो, डीएसपी मयंक तिवारी, नीरज पाल, एसआई रवि शाक्य, एसआई उत्तम मस्तकार, एसआई राकेश सारेयाम, एसआई छत्रपाल धुर्वे, एएसआई अरुण यादव, दीपक कटियार, तरुण पटेल, आर. अनिरुद्ध यादव, आर. उज्जवल दुबे, आर. प्रदीप कहार, आर. विकास जैन, आर. विवेक टेटवार, आर. निर्मला, आर. प्रीति भारती, साइबर सेल के एसआई अश्विनी चौधरी, एसआई नवीन सोनकर, आर. राजेंद्र, आर. बलराम राजपूत, आर. दीपेन्द्र सिंह, आर. पंकज, आर. सचिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आरडी पब्लिक स्कूल में हुआ इंटर स्कूल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन

बैतूल। क्वालिटी एजुकेशन के साथ विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने में उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान आर.डी. पब्लिक स्कूल बैतूल द्वारा महती भूमिका अदा की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में इंटर स्कूल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का भव्य आयोजन किया गया। 8 से 11 दिसम्बर तक आयोजित चार दिवसीय टूर्नामेंट में 16 टीमों ने सहभागिता कर खिलाड़ियों ने अनुशासन, टीम भावना से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रोमांचक और कडे मुकाबले के बाद आरडी पब्लिक स्कूल और लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल की टीम फायनल में पहुची। फायनल मैच के दौरान कड़ी प्रतिस्पर्धा में एलएफएस की टीम विजेता एवं आर.डी. पब्लिक

स्कूल की टीम उपविजेता रही। आर.डी.पब्लिक स्कूल बैतूल द्वारा आयोजन इंटर स्कूल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में सी.एम.राइज आमला, आरडीसीसी बैतूल, आरडीपीएस बैतूल, आरडीपीएस मुलताई, विद्यार्थी पब्लिक स्कूल, एल.एफ.एस स्कूल बैतूल, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बिसनूर सहित 16 टीमों ने सहभागिता की। टूर्नामेंट में नॉक आउट, क्वार्टर फायनल, सेमीफायनल और फायनल मुकाबलो में खिलाडियों में खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना से उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शकों को अंत तक जोडे रखा। चार दिवसीय इंटर स्कूल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का समापन 11 दिसम्बर को हुए। समापन कार्यक्रम में अतिथियों बैतूल एसडीएम अभिजीत सिंह, सहायक आयुक्त विवके पांडे, डीएसपी सुश्री शेफा हाशमी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, जिला खेल अधिकारी धर्मेन्द्र पंवार, आर.डी. संस्थान की निदेशक श्रीमती ऋचु खण्डेलवाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को पुरूस्कृत किया। अतिथियों ने विजेता टीम एलएफएस को 10001 रूपए नगद पुरूस्कार व ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम आर.डी.पब्लिक स्कूल बैतूल को 5001 रूपए नगद पुरूस्कार एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया।

6 माह से फरार चोरी का आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। शाहपुर पुलिस ने चोरी के मामले में लगभग 06 माह से फरार आरोपी टीना उर्फ नेहा यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार फरियादिया तमन्ना गुरु रागिनी नायक (39) निवासी ठाकुर मोहल्ला शाहपुर ने थाना शाहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह 30 जून 2025 को लाखनवाड़ी परतवाड़ा गई थी। 4 जुलाई को वापस घर आकर देखने पर उसके घर के अंदर की आलमारी का समान बिखरा हुआ था। आलमारी में रखे नगद व जेवरात चोरी जाने की शिकायत थाना मे दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने धारा 305(ए) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया। फरियादी से पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि फरियादी के घर में करीब 15 दिवस पूर्व संदेही शाहिबा उर्फ रेहान व नेहा यादव उर्फ टीना किन्नर रुके हुये थे। घटना के समय भी संदेही फरियादी के घर आये थे। संदेह के आधार पर शाहिबा उर्फ रेहान को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ करने पर अपने साथी नेहा उर्फ टीना यादव के साथ फरियादिया के घर चोरी करना स्वीकार किया। शाहिबा उर्फ रेहान यादव (22) निवासी चन्दन नगर की हाल इलयास कालोनी खजराना जिला इंदौर को पूर्व मे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष के समक्ष पेश किया गया था। घटना का अन्य आरोपी नेहा उर्फ टीना यादव घटना दिनांक से फरार था, जो 11 दिसंबर को घोडाडोंगरी में रेलवे स्टेशन के मिला, जिसे समक्ष गवाहो के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानन्द शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संभाग प्रभारियों और मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठककर संगठनात्मक विषयों एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की।

किसी भी प्रदेश के किसान हों, हमारे लिए भगवान समानः शिवराज

नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे विस्तार से जानकारी दी। शिवराज सिंह ने कहा कि, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। देश के समग्र विकास के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। पहला उत्पादन बढ़ाना, दूसरा लागत घटाना, तीसरा फसलों के उचित दाम, चौथा नुकसान की भरपाई, पांचवा फसलों का विविधिकरण और छंटवा प्राकृतिक खेती। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, मुझे बताते हुए खुशी है कि, वर्ष 2014 से 2024 तक 44त्न खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उत्पादन बढ़े, उसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सभी का उपयोग हो रहा है।

यूपीए ने कहा था संभव नहीं, एनडीए ने करके दिखाया- केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, एनडीए सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में वो काम कर दिखाया है, जिसे यूपीए सरकार ने असंभव बताया था। उन्होंने कहा कि, जब यूपीए की सरकार थी, तब यह साफ कहा गया था कि लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय करना संभव नहीं है। कैबिनेट नोट में लिखा गया था कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। मैंने उस कैबिनेट नोट की प्रति भी इसी सदन में रखी थी, लेकिन एनडीए सरकार ने 2019 में फैसला लिया कि एमएसपी अब लागत पर 50त्न मुनाफा जोड़कर ही निर्धारित की जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि, यूपीए शासन में किसानों को मिलने वाला लाभ बहुत कम था। उस समय धान की ए2+ एफएल लागत 1579 रुपए थी और एमएसपी 2369 रुपए, यानी 50त्न से अधिक मुनाफा आज हमारी सरकार दे रही है, लेकिन यूपीए के दौर में मक्का, ज्वार, रागी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी लगभग हर फसल पर मुनाफा बेहद कम था। ज्वार पर केवल 18 प्रतिशत, रागी पर 12 प्रतिशत, मूंग पर 19 प्रतिशत, उड़द पर 37प्रतिशत और सूरजमुखी पर सिर्फ 23प्रतिशत लाभ मिलता था। वहीं गेहूं पर ए2+ एफएल लागत 1249 रुपए होती है, और एनडीए सरकार ने एमएसपी 2585 रुपए तय की है। यानी किसानों को 109 प्रतिशत मुनाफा दिया जा रहा है। इसी तरह जौ की लागत 1361 रुपए, एमएसपी 2150 रुपए– 58 प्रतिशत मुनाफा, मसूर की लागत 3705 रुपए, एमएसपी पर 89 प्रतिशत लाभ और सरसों/रेपसीड की लागत 3210 रुपए, एमएसपी 6200 रुपए, 93प्रतिशत मुनाफा किसानों को मिल रहा है।

केन्द्र सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने में पूरी प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वर्ष 2019 में हमने तय किया कि एमएसपी लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर घोषित की जाएगी, ताकि किसान को लाभकारी दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2004 से 2014 के बीच धान की खरीदी 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हुई थी, जबकि 2014 से 2025 के बीच हमारी सरकार ने 89 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। इसी तरह गेहूं की खरीद 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन हो गई है। दलहन को लेकर शिवराज सिंह ने कहा कि, पहले तो स्थिति ऐसी थी कि ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था, उस समय दलहन की खरीद सिर्फ 6 लाख 29 हजार मीट्रिक टन थी। आज हमारी सरकार इसे बढ़ाकर 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन तक ले आई है। तिलहन की खरीद पहले 47 लाख 75 हजार मीट्रिक टन थी, अब 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। जूट, कोपरा और कपास मिलाकर पहले 35 लाख 47 हजार मीट्रिक टन खरीदी जाती थी, आज यह बढ़कर 81 लाख मीट्रिक टन हो गई है।

कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण

कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर विदिशा श्री अंशुल गुप्ता ने आज दोपहर में करीब दो बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय व्यवस्था, भंडारण, सामग्री वितरण, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा उपस्थिति प्रणाली सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रमुख निर्देश

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा जो प्रमुख निर्देश दिए गए हैं उनमें महामारी नियंत्रण कक्ष अलमारियों में रखी नस्तियों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। सभी नस्तियों की सूची तैयार कर अलमारी के ऊपर चस्पा की जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेज आसानी से खोजे जा सकें। आयुष्मान कार्ड वितरणकार्यालय में बड़ी मात्रा में आयुष्मान कार्ड पाए जाने पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इन कार्डों को तत्काल संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को वितरित किया जाए।

जिला वैक्सीन कोल्ड चैन स्टोर

निरीक्षण में वैक्सीन का स्टोरेज पूर्णतः व्यवस्थित पाया गया। स्टोर की उपयोगिता एवं उपलब्धता पर एक प्रेस नोट तैयार कर जिला जनसंपर्क कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए।

अनुपयोगी वाहन

कार्यालय परिसर के पीछे तीन पुराने वाहन (टाटा सुमो, बोलेरो एवं वेन) अनुपयोगी अवस्था में खड़े मिले। कलेक्टर ने इनके नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। जिला ई-औषधि भंडार गृह में अनियमितताएँ निरीक्षण में कई सामग्री वाटर कूलर ,गीजर ऑफिस चेयर,श्री-सीटर चेयर,बेड साइड स्टूल प्राप्ति तिथि संदर्भ में पूछताछ की गई है। भंडार गृह में प्राप्त तो हुई थीं, लेकिन स्टोर प्रभारी श्री करीम उद्दीन (मूल पदरू फार्मासिस्ट) द्वारा इन्हें नर्सिंग कॉलेज या संबंधित ब्लैको वितरित नहीं किया गया।

इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने उन्हें तत्काल स्टोर प्रभारी पद से हटाने के निर्देश दिए। न्यू बॉर्न किट का वितरण भंडार गृह में उपलब्ध न्यू बॉर्न किट तुरंत संबंधित सीएससी को वितरित करने के निर्देश दिए गए। कर्मचारी नेमप्लेट और कार्य सूचीसभी अधिकारी-कर्मचारियों के कक्ष में नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं शाखा का नाम अंकित नेमप्लेट लगाने के निर्देश।प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची भी प्रदर्शित करने को कहा गया।

अभिलेख प्रबंधन

कार्यालय में उपलब्ध अलमारी के अन्दर रखे समस्त अभिलेखध्पंजियों की सूची बनाकर अलमारी के ऊपर चस्पा की जाये, ताकि शाखा लिपिक की अनुपस्थिति में अन्य उपस्थित कर्मचारी उक्त नस्ती, पंजी को आसानी से तलाश कर उपलब्ध करा सके। कार्यालय में अनुपयोगी अभिलेखो, समान के विनिष्टीकरण की कार्यवाही हेतु नियमानुसार दल गठित कर विनिष्टिकरण की कार्यवाही करे। कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियो, कर्मचारियो की उपस्थिति वॉयोमैट्रिक, सार्थक एप्प के माध्यम से दर्ज की जाये। ई-अटैन्डेंस रिपोर्ट के आधार पर वेतन आहरण किया जाये।

शासकीय कार्यालयों को आईएसओ 9001 सर्टिफाइड कराए जाने हेतु अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट कार्यालय कम्पोजिट भवन में स्थित शासकीय कार्यालयों को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार प्रमाणित करने के लिए कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें क्वालिटी रिसर्च फाउंडेशन के लीड ऑफिसर श्री अजय त्रिपाठी द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों को आईएसओ 9001 के मानकों के अनुरूप कार्यालयों में कार्यकुशलता, पारदर्शिता, फाइल संधारण और सेवा वितरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में एसडीएम श्री मनीष शर्मा सहित अनेक विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन 9001 एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र है जो यह दर्शाता है कि किसी संस्था, संगठन या शासकीय कार्यालय द्वारा सेवा या प्रबंधन प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित और लागू किया है। आईएसओ सर्टिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि संस्था के काम करने के तरीके और प्रक्रियाएँ वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप हैं।

संक्षिप्त समाचार

जिला नजूल निर्वतन समिति की बैठक कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। जिले में शासकीय विभागों एवं उपक्रमों को विकास कार्यों के लिए भूमि आवंटित किए जाने हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला नजूल निर्वतन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुविभागवार भूमि आवंटन संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में कस्बा बेगमगंज स्थित भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 1.174 हैक्टेयर में से लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट प्रोजेक्टर फॉर एसटीपी कंस्ट्रक्शन हेतु मप्र शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नाम 2500 वर्गमीटर भूमि हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार कस्बा उदयपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 1.032 हेक्टेयर में से लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट परियोजना के लिए मप्र शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दो हजार वर्गमीटर भूमि हस्तांतरित किए जाने और उदयपुरा कस्बा में ही खसरा क्रमांक 326 रकबा 0.567 हेक्टेयर भूमि में से मीट मार्केट हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नाम 0.111 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

समाजसेवा की अनोखी मिसाल - बालक जीत चांडक ने जन्मदिन पर रेड क्रॉस को दिया 5100 रुपये का डोनेशन

सीहोर (निप्र)। सीहोर निवासी बालक जीत चांडक ने अपने जन्मदिन के अवसर को समाजसेवा के नाम समर्पित करते हुए एक अनोखी मिसाल पेश की। जीत ने वीवीएम प्रतियोगिता में प्राप्त 5100 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक रेड क्रॉस सोसायटी के लिए कलेक्टर श्री बालागुरू के. को सौंपा। जीत के पिता श्री विपुल चांडक ने बताया कि जीत ने पिछले वर्ष राज्य स्तरीय वीवीएम प्रतियोगिता में टॉप किया था और यह राशि जीती थी, जिसे उसने विशेष रूप से समाजसेवा के उद्देश्य से सुरक्षित रखा था। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने बालक जीत के इस प्रेरणादायक कदम की सराहना करते हुए कहा कि कम उम्र में इस तरह की सामाजिक भावना अत्यंत प्रशंसनीय है। जीत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह नागरिकों के लिए भी एक प्रेरणा है।

सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करने पहुंचे सहरिया नागरिक

विदिशा (निप्र)। गांव की पक्की सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने पर सिरोंज तहसील की ग्राम पंचायत दामोदरखेड़ी के ग्राम ओखलीखेड़ा में रहने वाले सहरिया समुदाय के नागरिकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। ग्राम ओखली खेड़ा के श्री नईम खान के साथ श्री अमर सिंह सहरिया, अशोक वाल्मीकि, खुमान सिंह सहरिया और दरियाब सिंह अहिरवार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। जिला प्रशासन का धन्यवाद देने पहुंचे सहरिया समुदाय के नागरिकों ने बताया कि उनके गांव ओखलीखेड़ा में रोड से आधा किलोमीटर की दूरी पर सहरिया समुदाय के 50 घर हैं। इस बस्ती से ग्राम धरमपुर और कोरबासा जाने का रास्ता एवं रोड से आदिवासी बस्ती का जो रास्ता है वह रोड से बस्ती तक जाने के लिए बरसात के समय में अत्यधिक कीचड़ युक्त होता था। घुटने-घुटने तक कीचड़ होती थी जिसके कारण इस बस्ती के बच्चे, महिलाएं और वृद्धजनों को दूसरे गांव में आने-जाने व बीमारी के समय मरीजों व गर्भवती माताओं को लाने ले जाने में बड़ी परेशानियां होती थी। इस मामले को जब जिला प्रशासन और कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के संज्ञान में लाया गया तो कलेक्टर श्री गुप्ता ने इस मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर आवश्यक कार्यवाही पूरी कराई इसके उपरांत इस गांव में सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

वन मण्डलाधिकारी द्वारा शमशाबाद परिक्षेत्र का औचक निरीक्षण, अवैध वृक्ष कटाई उजागर - दो वनरक्षक निलंबित

विदिशा (निप्र)। वन मण्डलाधिकारी विदिशा श्री हेमन्त यादव द्वारा आज वन परिक्षेत्र शमशाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बीट करमेढ़ी एवं बीट गोकलपुर में अवैध वृक्ष कटाई की घटनाएँ पाई गईं, जिन पर तत्काल संज्ञान लिया गया। औचक निरीक्षण के समय बीट करमेढ़ी के बीटगार्ड मनोज शर्मा, वनरक्षक तथा बीट गोकलपुर के बीटगार्ड राहुल दांगी, वनरक्षक अपने-अपने मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए।

फसल विविधिकरण की दिशा में रिनिया क्षेत्र के कृषक अग्रसर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में विदिशा जिले में निरंतर नवाचार आधारित कृषि पहल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड नटेरन की ग्राम पंचायत रिनिया के कृषकों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए चिया सीड्स एवं कलौंजी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को बड़े पैमाने पर अपनाया है।

प्रेरणा स्त्रोत : ग्राम के कृषक का नवाचार बना प्रेरणा स्त्रोत ग्राम रिनिया के प्रगतिशील कृषक श्री यशवंत तिवारी ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व एक कृषक मित्र से मिली प्रेरणा के आधार पर उन्होंने 1 हेक्टेयर क्षेत्र में चिया सीड्स की खेती की शुरुआत की थी। समय के साथ उन्होंने ग्राम के अन्य कृषकोंकृ मोहनबाबू तिवारी, बृजेश तिवारी, राधेश्याम तिवारी, धनराज कुशवाह, कैलाश अहिरवार, राहुल मालवीय, रामस्वरूप कुशवाह, सुन्दरसिंह कुशवाह एवं नारायणसिंह कुशवाहकृको भी इस नई फसल योजना से जोड़ा।

रकबा: 1 से 50 हेक्टेयर तक पहुँचा चिया सीड्स का रकबा: श्री तिवारी के अनुसार, इस वर्ष रिनिया क्षेत्र में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में चिया सीड्स तथा 30 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कलौंजी की खेती की गई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्राम में फसल विविधिकरण की ओर तेजी से सकारात्मक बदलाव हो रहा है।

अधिक लाभ

कम लागत में अधिक लाभ : क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी श्री राघवेंद्र अहिरवार एवं श्री अभिषेक जैन द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार,एक एकड़ में चिया सीड्स की खेती पर लगभग 15,000 से 20,000 रुपये तक की लागत आती है,जबकि उत्पादन का बाजार मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार यह फसल परंपरागत फसलों की तुलना में अत्यधिक लाभदायक साबित हो रही है। औषधीय फसलों की ओर बढ़ेगा रुझान, अकरकरा की तैयारी श्री यशवंत तिवारी ने आगे बताया कि खरीफ 2026 से सोयाबीन जैसी परंपरागत फसलों के स्थान पर वे औषधीय महत्व वाली फसल अकरकरा को शामिल करेंगे। इस फसल की बाजार मांग, औषधीय उपयोगिता एवं उच्च मूल्य को देखते हुए उन्होंने अन्य कृषकों से भी ऐसी फसलों को अपनाने की अपील की है।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश

बैतूल (निप्र)। केंद्र सरकार के ट्राईफेड द्वारा 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आदि बाजार का भव्य आयोजन किया जाएगा। आदि बाजार में प्रदेश की प्रचलित महेश्वर और चंदेरी साड़ियों से लेकर बांस कला, सजावटी पौधों की दुकान, वूलन क्लॉथ्स, हैंडलूम, फारेस्ट प्रोडक्ट्स, विभिन्न शिल्प और बैतूल जिले की पहचान बन चुके भरेवा शिल्प के हैंडीक्राफ्ट यहां लोगों को देखने और खरीदने को मिलेंगे।

इसके साथ ही फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिलेट से बने पारंपरिक और नवीन उत्पादों के 15 स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं ट्रायफेड के 25 स्टॉल, एनआरएलएम के 10 स्टॉल लगाए जाएंगे। आदि बाजार में छोटे-छोटे झूले और फन एक्टिविटीज भी आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर ट्राइबल के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 21 से 26 दिसंबर तक लगेगा आदि बाजार

होंगे। बुधवार को कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने स्टेडियम पहुंचकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आदि बाजार का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी तैयारियां तय समय-सीमा में पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने नगर पालिका को आदि बाजार में लाइटिंग , सफाई और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम को आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को स्थानीय जनजातीय कला पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण का सफल संचालन

विदिशा (निप्र)। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पशुपालकों की आय संवर्धन तथा वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान (द्वितीय चरण) के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि प्रशिक्षण को प्रभावी एवं परिणाममुखी बनाने हेतु प्रतिभागियों की संख्या को नियंत्रित रखा जाए। निर्देशानुसार प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में अधिकतम 30 प्रतिभागियों को ही शामिल करने का प्रावधान किया गया, ताकि प्रतिभागियों को विषय विशेषज्ञों से बेहतर संवाद, मार्गदर्शन और तकनीकी जानकारी मिल सके। निर्देशों के अनुरूप जिले में प्रशिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करते हुए एक विख (विकासखंडध्पशु चिकित्सा खंड) के लिए एक दिवस का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। चरणबद्ध रूप से सभी विखों के पशुपालकों, पशु चिकित्सा कर्मियों एवं संबंधित हितधारकों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादन में नवीन तकनीकों का उपयोग, पोषक तत्वों से युक्त चारे का वैज्ञानिक प्रबंधन, पशुओं में रोग नियंत्रण, दुग्ध प्रसंस्करण, विपणन के नवीन आयाम तथा पशुपालकों की आय दोगुनी करने हेतु आवश्यक उपायों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों द्वारा व्यवहारिक प्रदर्शन एवं परामर्श भी दिया गया। जिला स्तर पर आयोजित इस प्रशिक्षण से प्रतिभागियों में उत्साह देखा गया तथा उपस्थित पशुपालकों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताया। आगामी दिनों में अभियान के अंतर्गत शेष विखों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निर्धारित तिथियों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

स्व-सहायता समूह से जुड़कर अनीता बाई के जीवन में आया बदलाव

रायसेन (निप्र)। प्रदेश में स्व-सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। इससे न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रही है। रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के ग्राम सिल्ली निवासी श्रीमती अनीता बाई के जीवन में भी स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद बदलाव आया है। कभी आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहीं अनीता बाई स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के बाद आत्मनिर्भर हो गई हैं तथा परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में भी वृद्धि हुई है। श्रीमती अनीता बाई ने बताया कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने से पहले उनकी स्थिति ठीक नहीं थी।

लाड़ली बहना योजना बन रही महिलाओं की आर्थिक मजबूती, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का नया आधार

सीहोर (निप्र)। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' लगातार बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसके योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश की लाड़ली बहनों को 1500 रूपये प्रतिमाह की राशि उनके खाते में अंतरित की जा रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता ने महिला शक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। महिलाओं को न केवल नियमित सहायता मिल रही है, बल्कि वे अपने परिवार, बच्चों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं में भी अधिक आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। सीहोर की फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी श्रीमती दीपा सिलावट बताती हैं कि योजना से मिलने वाली राशि ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले स्वयं की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें परेशानी होती थी और अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन योजना लागू होने के बाद उन्हें आर्थिक मजबूती मिली और वे स्वयं की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रही हैं। दीपा सिलावट कहती हैं कि नियमित आर्थिक सहायता से उनके घर की व्यवस्था में स्थिरता आई है और बच्चों की शिक्षा में भी वे सहयोग कर पा रही हैं। उनका कहना है कि यह योजना न केवल आर्थिक लाभ देती है बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। प्रदेशभर में इस योजना ने लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना आज महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण पहल बन गई है। इस योजना के लिए श्रीमती दीपक सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद दिया है।

सीईओ जिला पंचायत ने महुआखेड़ी तकीपुर शाला में पीएम पोषण योजना एवं माँ की बगिया का निरीक्षण कर विद्यार्थियों संग मध्याह्न भोजन किया

सीहोर (निप्र)। प्रधानमंत्री पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यपालन अधिकारीजिला पंचायत सीहोर श्रीमती सर्जना यादव ने शासकीय माध्यमिक शाला महुआखेड़ी तकीपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीईओ नेमाँ की बगिया का अवलोकन किया तथा शाला में कार्यरत समूह सदस्यों और रसोइयों से भोजन की गुणवत्ता, सामग्री उपलब्धता एवं संचालन प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया और भोजन की गुणवत्ता की सराहना की। इस अवसर पर शाला में शिक्षक एवं जनभागीदारी समिति के सहयोग से निर्मित मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण भी किया गया। सीईओ श्रीमती यादव ने निर्माण कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनभागीदारी के सहयोग से विद्यालयों के विकास कार्य तेजी से पूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने विद्यालय स्टाफ, समूह सदस्य, रसोइयों तथा उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सामुदायिक सहभागिता से शिक्षा एवं पोषण योजनाएँ और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित की जा सकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं नेशनल लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

विदिशा (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस तथा आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में किया जा रहा है। जिला अभिभाषक संघ कार्यालय में बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेख सलीम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ विशेष न्यायाधीश श्री जी. सी. शर्मा, अन्य न्यायिक अधिकारीगण, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मानवाधिकार दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए हुई। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेख सलीम ने उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गरिमा , स्वतंत्रता एवं समानता की रक्षा करने वाले मूल अधिकार हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से इन अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया।

न्यायाधीश ने उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सक्रिय भागीदारी का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय तक सरल पहुँच का प्रभावी माध्यम है, जिससे आमजन के लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान होता है। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं को लोक अदालत की प्रकिया, उसके लाभ तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। शिविर में उपस्थित अधिवक्ताओं एवं सदस्यों ने मानवाधिकार संरक्षण तथा लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सहयोग का संकल्प व्यक्त किया। विधिक जागरूकता शिविर का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम के आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला अभिभाषक संघ का विशेष सहयोग रहा इस अवसर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री संतोष शर्मा, सचिव श्री राजेन्द्र सिंह दांगी समेत अन्य पदाधिकारी व अधिवक्तागण मौजूद रहे।

मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता खिलाड़ियों ने दिखाया दम

विदिशा (निप्र)। सांसद खेल महोत्सव 2025 में आयोजित खेल गतिविधियों के अंतर्गत आज बुधवार को जिला खेल परिसर स्टेडियम विदिशा में विदिशा विधानसभा के 5 ग्रामीण मंडलों की कबड्डी की टीमों की प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिसमें मंडल के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया एवं खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन ने उपस्थित खिलाड़ियों से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने एवं जीवन में खेलों का महत्व बताते हुए हमेशा खेल भावना के साथ हर कार्य करने की अपील की। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा, जनपद अध्यक्ष विदिशा श्री वीर सिंह रघुवंशी, श्री प्रशांत खत्री, श्री दिनेश कुशवाहा, श्री सुरेंद्र चैहान, श्री अंकित दुबे उपस्थित रहे। जिला खेल अधिकारी श्री प्रदीप सिंह रावत ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव 2025 अंतर्गत आज जिला खेल परिसर में आयोजित मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बेसनगर मंडल एवं दुर्गा नगर मंडल की बालक एवं बालिका वर्ग में 10 टीमों ने भाग लिया। जिनमें मध्य मैच हुए। कबड्डी प्रशिक्षक श्रीमती ज्योति ठाकुर श्री अरविंद सिंह राजपूत श्री बीएस बुंदेला श्री रविकांत नामदेव श्रीमती सपना शर्मा ,मयूर भार्गव, अर्चना किरार, श्री अजय चैहान श्री योगेश धुर्वे श्री धीरेंद्र मिश्रा आदित्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव समोई (झाबुआ) के श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव में भोपाल से वर्चुअली हुए शामिल

झाबुआ-निमाड़ में आज बरस रहा है आनंद

श्रीकृष्ण पाथेय में जोड़ेंगे धार-झाबुआ में मौजूद भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित स्थानों को

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि धार और झाबुआ में भगवान श्रीकृष्ण की स्मृतियों से संबद्ध स्थानों को श्रीकृष्ण पाथेय में शामिल कर तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंने झाबुआ के ग्राम समोई में आयोजित श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज झाबुआ-निमाड़ में आनंद बरस रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव में भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए। समोई में कार्यक्रम स्थल पर संतों के साथ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, धार-झाबुआ सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन अद्भुत रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। भगवान श्रीकृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले प्रणामी सम्प्रदाय के द्वारा आयोजित श्रीकृष्ण प्रणामी महोत्सव सर्वधर्म संभाव और सनातन मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि 400 वर्ष पूर्व सदुरू श्री देवचन्द्र जी महाराज के द्वारा प्रारंभ किये गये प्रणामी संप्रदाय के लिये वे आज अखण्ड सनातन परंपरा का प्रकाश स्तंभ है। प्रणामी सम्प्रदाय का व्यापक प्रचार-प्रसार प्राणानाथ स्वामी और उनके शिष्य महाराज छत्रसाल ने किया था। प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख 3 धामों में से एक धाम पद्मावती पुरी है, जो कि हमारे प्रदेश के पन्ना शहर में है। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म एक ऐसा मार्ग है, जो कृष्ण भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और सार्वभौमिक भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह महोत्सव परंपरा, भक्ति, समाज सुधार और आध्यात्मिक एकता का अद्भुत संगम है। उन्होंने प्रणामी सम्प्रदाय के अनुयायियों औरसमाज के लोगों को धर्म महोत्सव की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कामना की कि भगवान श्रीकृष्ण, श्यामाजी महारानी, सदुरू देवचन्द्र, स्वामी प्राणनाथ, वृंदावन दास महाराज और नटवरदास महाराज की सदैव सभी पर कृपा बनी रहे।

प्रमुख बिन्दु

- धार और झाबुआ में भगवान श्रीकृष्ण की स्मृतियों से संबद्ध स्थानों को श्रीकृष्ण पाथेय में शामिल कर तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जायेगा।
- समोई में कार्यक्रम स्थल पर संतों के साथ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, धार-झाबुआ सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान मौजूद रही।
- भगवान श्रीकृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले प्रणामी सम्प्रदाय के द्वारा आयोजित श्रीकृष्ण प्रणामी महोत्सव सर्वधर्म संभाव और सनातन मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है।
- 400 वर्ष पूर्व सदुरू श्री देवचन्द्र जी महाराज के द्वारा प्रारंभ किये गये प्रणामी संप्रदाय के लिये सदुरू महाराज जी अखण्ड सनातन परंपरा का प्रकाश स्तंभ है।
- प्रणामी सम्प्रदाय का व्यापक प्रचार-प्रसार प्राणानाथ स्वामी और उनके शिष्य महाराज छत्रसाल ने किया था।
- प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख 3 धामों में से एक धाम पद्मावती पुरी है, जो कि हमारे प्रदेश के पन्ना शहर में है।
- यह महोत्सव परंपरा, भक्ति, समाज सुधार और आध्यात्मिक एकता का अद्भुत संगम है।

प्रदेश में टेम्प्रेचर का टॉर्चर...इंदौर पचमढ़ी से भी ठंडा रहा, 5.2 डिग्री रहा पारा

भोपाल, ग्वालियर में भी पारा लुढ़का, 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और टेम्प्रेचर का टॉर्चर जारी है। शुक्रवार की रात कई शहरों में पारा 5 डिग्री के आसपास रहा। इंदौर शहर में 5.2 डिग्री रहा। इतना ही तापमान पचमढ़ी में भी दर्ज किया गया। रात में भोपाल और ग्वालियर में पारे में गिरावट हुई। भोपाल में 6.5 डिग्री, ग्वालियर में 9.1 डिग्री, उज्जैन में 9 डिग्री और जबलपुर में पारा 8.4 डिग्री रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, बीती रात अधिकांश शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे ही रहा। राजगढ़ में 5.2 डिग्री, नौगांव में 6.4 डिग्री, उमरिया में 6.6 डिग्री, रीवा में 7 डिग्री, मलाजखंड में 7.2 डिग्री, मंडला में 7.6 डिग्री, रायसेन, शिवपुरी-नरसिंहपुर में 8 डिग्री, बैतूल में 8.5 डिग्री, छिंदवाड़ा-खजुराहो में 9 डिग्री, सतना में 9.1 डिग्री, टीकमगढ़-रतलाम में 9.5 डिग्री, दमोह में 9.8 डिग्री और दतिया में 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

मध्यप्रदेश उत्सव में गुदममबाजा नृत्य धुलिया गोंड़ जनजाति के पारंपरिक वाद्य नृत्य की प्रस्तुति।

10 हजार फीट से छलांग लगाकर देखें महाकाल की नगरी

पहले दिन 100 से अधिक पर्यटकों ने कराया रजिस्ट्रेशन, दो माह चलेगा स्काई डाइविंग फेस्टिवल

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने शुक्रवार से स्काई डाइविंग फेस्टिवल के पांचवें संस्करण की शुरुआत कर दी। दताना एयरस्ट्रिप पर शुरू हुआ यह आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पर्यटक 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी का अद्भुत दृश्य देख सकेंगे।

दताना एयरस्ट्रिप पर एमपी पर्यटन बोर्ड के अपर प्रबंध संचालक अभय अरविंद बेडेकर और संयुक्त संचालक (एडवेंचर) डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव ने फेस्टिवल की शुरुआत की। स्काई डाइविंग के पहले ही दिन उज्जैन और अन्य शहरों से करीब 100 एडवेंचर प्रेमियों ने पंजीयन कराया। बेडेकर ने बताया कि यह स्काई डाइविंग का पांचवां संस्करण है। इसमें लोग 10 हजार फीट की ऊंचाई से रोमांचक अनुभव ले सकेंगे। देश के विभिन्न बड़े शहरों से एडवेंचर प्रेमी उज्जैन पहुंच रहे हैं।

30 हजार रुपए प्लस जीएसटी फीस

पिछले चार सफल आयोजनों और बढ़ती मांग को देखते हुए इस साल फेस्टिवल को दो माह तक किया जा रहा है। चार संस्करणों में 700 से अधिक लोगों ने स्काई डाइविंग का अनुभव लिया था। इस बार डाइविंग की फीस 30 हजार रुपए प्लस जीएसटी रखी गई है। गतिविधि प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इच्छुक प्रतिभागी अपनी बुकिंग वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से सौजन्य भेंट की।

एनटीपीसी पर रिहंद डैम में जहरीला पानी छोड़ने का आरोप

दो दिन में सैकड़ों मछलियों की मौत, अधिकारियों ने जांच के लिए भेजे सैंपल

सिंगरौली (नप्र)। सिंगरौली में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रिहंद डैम में पिछले दो दिनों से मछलियों की लगातार मौत हो रही है। गुरुवार शाम एक वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया। इसमें सिंगरौली से सटे डैम के हिस्से में सौ से अधिक मछलियां मृत पाई गईं।

यही से फिल्टर प्लांट के लिए सप्लाई होता है पानी- घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। क्योंकि सिंगरौली नगर निगम इसी स्थान से पीने के पानी को फिल्टर प्लांट तक भेजता है। ऐसे में पानी की गुणवत्ता और प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।

एनटीपीसी पर जहरीला पानी छोड़ने का आरोप- आरोप है कि एनटीपीसी विंध्याचल और एनटीपीसी शक्ति नगर की ओर से डैम में जहरीला या फ्लाई ऐश मिश्रित पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि, एनटीपीसी प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विवाद बढ़ने के बाद शुक्रवार को सिंगरौली जिला प्रशासन, मत्स्य विभाग और एनटीपीसी की विशेषज्ञ टीम ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश वाले हिस्से में जांच की। टीमों ने मौके से पानी के नमूने लिए और मृत मछलियों की स्थिति का जायजा लिया।

पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए

सिंगरौली के एसडीएम सुरेश जाधव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ मछलियां डैम में तैरती मिलीं, जबकि कई किनारे पर मृत अवस्था में थीं। पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा।

जनसंपर्क अधिकारी बोले-कोई जहरीला पानी डैम में नहीं छोड़ा जाता

एनटीपीसी के जनसंपर्क अधिकारी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का जहरीला पानी डैम में नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाला पानी रिहंद डैम से ही लिया जाता है और इसे वापस छोड़ने की बात आधारहीन है। उन्होंने वायरल वीडियो की समय और परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए।

फिलहाल, पानी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही मछलियों की मौत की असली वजह सामने आएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है।

बिजलीकर्मी को गोली मारकर एक पैर से भागा दिव्यांग

आर्टिफिशियल लेग पर लिखे नाम से पकड़ाया, बोला- बदला लेने के लिए फायर किया

सतना (नप्र)। सतना में दिव्यांग ने लूट के इरादे से बिजलीकर्मी के सीने में गोली मार दी। बिजलीकर्मी ने उससे कट्टा छीन लिया। इसी दौरान दिव्यांग का आर्टिफिशियल पैर निकल गया। फायरिंग की आवाज सुन लोग भी इकट्ठा हो गए, उन्हें लगा कि आरोपी भाग नहीं पाएगा। लेकिन वह एक पैर से ही कूदते हुए फरार हो गया। घटना सिटी कोतवाली इलाके के प्रेम नगर अंडरपास के ऊपर रेलवे लाइन किनारे गुरुवार की है। आरोपी भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद आरोपी ने एक पैर से भागते हुए कई राहगीरों से लिफ्ट भी मांगी थी। गोली लगने के बाद भी रामनरेश खुद सिटी कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।

आर्टिफिशियल पैर पर लिखे नाम से पकड़ाया- जो कृत्रिम पैर मौके से मिला, उस पर 'राजेंद्र' नाम लिखा हुआ है। इसी आधार पर पुलिस ने धवारी, राजेंद्र नगर और आसपास के क्षेत्रों में दिव्यांग

लोगों से पूछताछ की।

पूछताछ में पता चला कि राजेंद्र कुमार सोनी नाम का दिव्यांग संग्राम नगर में रहता है। कोतवाली पुलिस ने उसे शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। वह वारदात के बाद ऑटो में सवार होकर अपने घर संग्राम कॉलोनी चल गया था।

पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि ट्रेन में उसका विवाद हो गया था। जिसके बाद बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। कट्टा उसे कहां से मिला, वारदात को अंजाम देन के बाद वह कहां-कहां गया, पुलिस इस बारे में पूछताछ कर रही है।

चचेरे भाई से प्यार करती थी बहन...

परिवार ने दूसरी जगह तय कर दी शादी, बारात आने से पहले दोनों ने दी जान

मुरैना (नप्र)। मुरैना जिले में एक युवक और युवती ने पेड़ पर एक ही दुपट्टे से फंदा लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि युवती की उसी दिन शादी होने वाली थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

रिश्ते में चचेरे भाई-बहन लगते थे दोनों- पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जौरा विकास खंड के तिलऊंआ गांव की रहने वाली भारती कुशवाहा (19) और रवि कुशवाहा (22) आपस में प्रेम करते थे। लेकिन दोनों एक ही परिवार से आते थे और रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। इस कारण परिजनों ने इनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और दोनों के मिलने पर रोक लगा दी थी। भारती के पिता ने बेटी की शादी मुरैना जिले के डाबी का पुरा गांव के गोलू कुशवाहा से तय कर दी थी जिससे दोनों नाराज थे।

घर में पूरी थी शादी की तैयारी

गौरतलब है कि घर में बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी। मंडप भी सज गया था। सारी रस्में निभाई जा रही थी और परिवार के लोगों को अचानक खबर मिली कि दुल्हन ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद सारे कार्यक्रम स्थगित हो गए। साथ ही परिवार में हर तरफ चीख पुकार मच गई। पोस्टमार्ट्म के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है।

गले में फंदा डालकर दी जान

उन्होंने बताया कि गोलू और भारती का विवाह गुरुवार 11 दिसंबर को होने वाला था और बारात भारती के गांव आनी थी। उससे पहले ही भारती ने रवि कुशवाहा के साथ गांव के पीछे नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

जौरा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) नितिन बघेल ने बताया कि एक ही दुपट्टे के दोनों छोर से दोनों ने फंदा लगा लिया। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। परिजन कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्ट्म के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच की जाएगी तथा परिजनों के बयान लिये जायेगें, तभी मामला कुछ स्पष्ट होगा।

पी.एच.डी शोध छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

शिक्षण सत्र 2025-26 के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

भोपाल(नप्र)। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2025-26 में पी.एच.डी. शोध छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विश्वविद्यालयों में अध्ययरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों के दिव्यांग शोधार्थियों से नवीन एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन मंगाए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को 5 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से आवेदन जमा करना होगा। नवीन आवेदन कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल एवं नवीनीकरण के लिए कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक में जमा करने होंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

पात्रता नियम

- शोधार्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, जिसका प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक होगा।
- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग वर्ग, जो पी.एच. डी. अनुसंधान के लिए पंजीकृत हो।
- एससी/एसटी वर्ग के आवेदकों के लिए माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दिव्यांग वर्ग के सभी आवेदकों के लिए भी अभिभावक की आय सीमा रूपये 8,00,000 निर्धारित है।
- सभी वर्गों के दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- एक समय में केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त की जा सकेगी। पहले से किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे शोधार्थी दोहरी छात्रवृत्ति नहीं ले सकेंगे।

ब्राह्मण बेटियों पर बयान देने वाले आईएएस को हटाया

केंद्र को बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजेगी सरकार, सीएम ने कृषि विभाग से जीएडी पूल में अटैच किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विवादों में घिरे आईएएस संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लेते हुए उनकी आईएएस सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का आदेश दिया है। सरकार वर्मा को चार्जशीट भी देगी।

देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में अटैच कर दिया गया है, जहां उनके पास न विभाग होगा, न कोई कार्य।

सरकार क्यों भेज रही है बर्खास्तगी का प्रस्ताव?- सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की रिपोर्ट में बताया गया कि वर्मा ने फर्जी और जाली

आदेश बनाकर आईएएस पद पर पदोन्नति ली थी। उनके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण अदालतों में लंबित हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया आईएएस प्रमोशन 'गलत और अवैध' माना गया है।

उन पर जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। सरकार का कहना है कि वर्मा द्वारा भेजा गया जवाब असंतोषजनक है। इन आधारों पर सीएम यादव ने कहा कि वर्मा को आईएएस सेवा में रखना 'अनुशासन और कानून व्यवस्था के खिलाफ' है।

हाल ही में दिए थे दो विवादित बयान- आईएएस संतोष वर्मा ने हाल के दिनों में दो बड़े विवादित बयान दिए थे। आईएएस संतोष वर्मा के बयान के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा था। कई जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था और कार्रवाई की मांग की थी। जगह-जगह वर्मा के पुतले भी फूंके गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद बड़े आंदोलन की भी तैयारी थी।

यह विवादित बयान दिए थे

1. ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणीः अजाक्स सम्मेलन में बोलेः जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।

2. हाईकोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए- एक अन्य वीडियो में कहा-एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं, हाईकोर्ट नहीं बनने दे रहा है कटऑफ मार्क्स जानबूझकर कम दिए जाते हैं।

14 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करने वाला था ब्राह्मण समाज

आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर नाराज ब्राह्मण और सर्व समाज ने 14 दिसंबर को सीएम हाउस घेराव पर मुहर लगाई थी। कांग्रेस, बीजेपी और सभी दलों के सर्व समाज के लोगों ने कहा कि पूरे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी धरना प्रदर्शन, पुतला दहन हो रहे हैं पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। 14 दिसंबर को पूरी ताकत से भोपाल में जुटकर सीएम हाउस का घेराव किया जाने वाला था।